RNI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

GARVI GUJARAT

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 263
दि. 24.01.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था में दरार: डब्ल्यूएचओ से अमेरिका की ऐतिहासिक विदाई

(जीएनएस)। न्यूयॉर्क। वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था के इतिहास में एक बड़ा और दूरगामी असर डालने वाला घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिका आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ से अलग हो गया है। इस फैसले के साथ ही जिनेवा स्थित डब्ल्यूएचओ मुख्यालय के बाहर से अमेरिकी ध्वज को हटा दिया गया, जो इस अलगाव का प्रतीक बन गया है। दशकों तक दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख स्तंभ रहा अमेरिका अब इस वैश्विक मंच का हिस्सा नहीं है। यह निर्णय केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य सहयोग, वैश्विक राजनीति और भविष्य की महामारियों से निपटने की रणनीति को प्रभावित करने वाला बड़ा मोड़ माना जा रहा है।

अमेरिका के इस फैसले की पृष्ठभूमि कोविड-19 महामारी से जुड़ी नाराजगी में छिपी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में लौटने के बाद जनवरी 2025 में एक शासकीय आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी के दौरान गंभीर स्तर पर कुप्रबंधन किया। ट्रंप प्रशासन का आरोप रहा है कि डब्ल्यूएचओ न तो समय पर चेतावनी देने में सफल रहा और न ही पारदर्शिता व जवाबदेही के मानकों पर खरा उतर पाया। उनके अनुसार, संगठन की नीतियों और फैसलों ने न केवल वैश्विक स्वास्थ्य संकट को गहराया, बल्कि अमेरिका जैसे देशों के राष्ट्रीय हितों को भी नुकसान पहुंचाया। इसी असंतोष ने अमेरिका को यह कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित किया।

हालांकि अमेरिका के डब्ल्यूएचओ से अलग होने की प्रक्रिया अचानक पूरी नहीं हुई। अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार, किसी भी सदस्य देश को संगठन छोड़ने के लिए एक साल पहले औपचारिक सूचना देनी होती है, जिसे अमेरिका ने पहले ही पूरा कर लिया था। अब जब यह प्रक्रिया औपचारिक रूप से समाप्त हो चुकी है, तब भी कई तकनीकी और कूटनीतिक चुनौतियां सामने बनी हुई हैं। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने खुद स्वीकार किया है कि अन्य देशों के

स्वास्थ्य डेटा तक पहुंच, वैश्विक निगरानी तंत्र में भागीदारी और अंतरराष्ट्रीय शोध सहयोग जैसे मुद्दों पर अभी पूरी तरह से समाधान नहीं निकल पाया है।

इस फैसले का सबसे बड़ा असर वित्तीय मोर्चे पर पड़ता दिख रहा है। दशकों से अमेरिका डब्ल्यूएचओ का सबसे बड़ा दानदाता रहा है। आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका हर साल औसतन 11.1 करोड़ डॉलर सदस्यता शुल्क के रूप में देता था, जबकि स्वैच्छिक योगदान के रूप में लगभग 57 करोड़ डॉलर प्रति वर्ष उपलब्ध कराता था। इसके अलावा, अमेरिका की तकनीकी विशेषज्ञता, शोध संस्थानों का सहयोग और वैज्ञानिक संसाधन संगठन की रीढ़ माने जाते थे। अब अमेरिका के बाहर होने से डब्ल्यूएचओ को न केवल भारी आर्थिक घाटे का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उच्च स्तरीय तकनीकी समर्थन से भी वंचित होना पड़ेगा।

विवाद का एक अहम पहलू अमेरिका पर बकाया राशि को लेकर भी है। डब्ल्यूएचओ के रिकॉर्ड के मुताबिक, अमेरिका पर करीब 13.3 करोड़ डॉलर का बकाया है, जो उसने 2024 और 2025 के लिए अपने वित्तीय दायित्वों के तहत भुगतान नहीं किया। संगठन का कहना है कि सदस्यता समाप्त होने के बावजूद यह राशि बकाया के रूप में बनी हुई है। वहीं ट्रंप प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि अमेरिका पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं बनती, क्योंकि सदस्यता छोड़ने से पहले ही उसने औपचारिक सूचना दे दी थी। इस मुद्दे पर आने वाले समय में कानूनी और कूटनीतिक खींचतान बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों और अंतरराष्ट्रीय नीति विश्लेषकों ने अमेरिका के इस कदम को वैश्विक स्वास्थ्य तंत्र के लिए एक बड़ा झटका बताया है। जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय के सार्वजनिक स्वास्थ्य कानून विशेषज्ञ लॉरेंस गोस्टिन ने इसे किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लिया गया अब तक का सबसे विनाशकारी फैसला करार दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के बाहर होने से भविष्य की महामारियों के खिलाफ वैश्विक प्रतिक्रिया कमजोर पड़ सकती है। डब्ल्यूएचओ की भूमिका केवल सलाह देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संगठन महामारी की निगरानी, शुरुआती चेतावनी, टीका वितरण और अंतरराष्ट्रीय समन्वय का अहम केंद्र रहा है। अमेरिका की गैरमौजूदगी से इन सभी क्षेत्रों में प्रभाव पड़ना तय माना जा रहा है।

इस फैसले का असर अमेरिका के भीतर भी महसूस किया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिकी वैज्ञानिकों, दवा कंपनियों और शोध संस्थानों को वैश्विक स्तर पर टीके और दवाएं विकसित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। डब्ल्यूएचओ के मंच के जरिए अमेरिका को दुनिया भर के स्वास्थ्य डेटा, शोध निष्कर्षों और आपातकालीन सूचनाओं तक सीधी पहुंच मिलती थी। अब इस नेटवर्क से बाहर होने के कारण अमेरिका को वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनानी होंगी, जो समय और संसाधन दोनों की मांग करेंगी।

अमेरिका के इस फैसले ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भी चिंता बढ़ा दी है। कई देशों का मानना है कि वैश्विक स्वास्थ्य जैसे विषय पर सहयोग की बजाय अलगाव का रास्ता चुनना दुनिया को और अधिक असुरक्षित बना सकता है। कोविड-19 ने यह दिखाया था कि वायरस सीमाओं को नहीं मानते और किसी एक देश की कमजोरी पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। ऐसे में डब्ल्यूएचओ जैसे मंच की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। दूसरी ओर, ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि अमेरिका डब्ल्यूएचओ से बाहर होकर भी वैश्विक स्वास्थ्य में अपनी भूमिका निभाता रहेगा, लेकिन अपने शर्तों और प्राथमिकताओं के आधार पर। उनका कहना है कि अमेरिका सीधे द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय समझौतों और अपने स्वयं के स्वास्थ्य कार्यक्रमों के जरिए दुनिया की मदद करेगा। हालांकि आलोचकों का मानना है कि यह दृष्टिकोण समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया की जगह बिखरे प्रयासों को बढ़ावा देगा।

कुल मिलाकर, अमेरिका का डब्ल्यूएचओ से अलग होना केवल एक संगठनात्मक बदलाव नहीं है, बल्कि यह वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था में एक गहरी दरार का संकेत देता है। आने वाले वर्षों में यह साफ होगा कि यह फैसला दुनिया को अधिक सुरक्षित बनाता है या नई चुनौतियों को जन्म देता है। इतना तय है कि इस ऐतिहासिक अलगाव के प्रभाव लंबे समय तक महसूस किए जाएंगे और वैश्विक स्वास्थ्य नीति पर इसकी छाया बनी रहेगी।

सुरक्षा की नई रूपरेखा: आगामी बजट में रक्षा तैयारियों को मिलेगी सबसे बड़ी धार

(जीएनएस)। नई दिल्ली। एक ऐसे समय में जब वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य तेजी से बदल रहा है और भारत की सीमाओं पर रणनीतिक सतर्कता पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गई है, केंद्र सरकार का आगामी आम बजट रक्षा क्षेत्र के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। संकेत मिल रहे हैं कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में रक्षा आवंटन साढ़े सात लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर सकता है। मौजूदा वित्त वर्ष में जहां रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ रुपये है, वहीं इस बार इसमें करीब 25 से 30 हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। प्रतिशत के लिहाज से यह वृद्धि लगभग 10 फीसदी के आसपास हो सकती है, लेकिन इसका वास्तविक महत्व केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि उस रणनीतिक संदेश में छिपा है, जो सरकार देश और दुनिया को देना चाहती है।

हाल के वर्षों में भारत ने न केवल अपनी सुरक्षा चुनौतियों को नए सिरे से परिभाषित किया है, बल्कि सैन्य क्षमता के लिहाज से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी बड़े कदम उठाए हैं। 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार की प्राथमिकता केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि सेनाओं को भविष्य के युद्धों के लिए तैयार करना भी उतना ही जरूरी है। आधुनिक युद्ध अब केवल पारंपरिक हथियारों से नहीं लड़े जाते, बल्कि इसमें तकनीक, साइबर क्षमता, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणालियों की अहम भूमिका होती है। यही कारण है कि इस बार के बजट में सेनाओं के आधुनिकीकरण और उनके बीच बेहतर तालमेल यानी एकीकरण पर विशेष जोर रहने की उम्मीद है।

सूत्रों के अनुसार, रक्षा बजट का सबसे बड़ा हिस्सा आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित किया जा सकता है, जो दो लाख करोड़ रुपये से भी ऊपर जा सकता है। चालू वित्त वर्ष में इस मद के लिए करीब 1.80 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान था, लेकिन 'आत्मनिर्भर भारत' की सोच को और मजबूती देने के लिए इसमें बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। सरकार का इरादा साफ है कि आने वाले वर्षों में रक्षा उपकरणों और प्रणालियों के आयात पर निर्भरता कम की जाए और घरेलू रक्षा उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जाए। स्वदेशी लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम, नौसैनिक प्लेटफॉर्म और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इस रणनीति का केंद्र बिंदु होंगे।

रक्षा बजट को जीडीपी के अनुपात में देखने की बहस भी हर साल तेज होती है। फिलहाल भारत का रक्षा व्यय सकल घरेलू उत्पाद के दो प्रतिशत से नीचे बना हुआ है और विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार भी यह इसी दायरे में रह सकता है। हालांकि तुलना के लिए अक्सर चीन का उदाहरण दिया जाता है, जिसका रक्षा बजट भी जीडीपी के लगभग दो प्रतिशत के आसपास ही है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था का आकार कहीं बड़ा होने के कारण वास्तविक राशि काफी अधिक हो जाती है। भारत सरकार का तर्क यह रहा है कि बजट केवल एक आधार है और जरूरत पड़ने पर रक्षा मंत्रालय को अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराए जाते हैं। बीते वर्षों में कई बार ऐसा देखा गया है कि बड़े सैन्य सौदों या आपात जरूरतों के लिए बजट से इतर मंजूरी देकर धनराशि जारी की गई है।

रक्षा बजट का एक बड़ा और संवेदनशील हिस्सा पेंशन से जुड़ा होता है। लाखों सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। चालू वित्त वर्ष में पेंशन के लिए लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इस बार 'वन रैंक वन पेंशन' के तहत पांच साल में होने वाली समीक्षा के कारण पेंशन मद में और बढ़ोतरी की संभावना है। इससे पूर्व सैनिकों को संशोधित दरों पर पेंशन का लाभ मिलेगा और सरकार के प्रति उनका भरोसा और मजबूत होगा। हालांकि इससे कुल रक्षा बजट पर दबाव भी बढ़ता है, लेकिन सरकार इसे आवश्यक और अपरिहार्य व्यय मानती है।

आगामी वित्त वर्ष और उसके बाद के वर्षों को देखते हुए भारत कई बड़े और महत्वपूर्ण रक्षा सौदों की तैयारी में है। नए लड़ाकू विमानों की खरीद, आधुनिक ड्रोन प्रणालियां, लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और तेजस लड़ाकू विमानों के लिए अत्याधुनिक जीई इंजनों का सौदा जैसे प्रस्ताव लंबे समय से चर्चा में हैं। इन परियोजनाओं के लिए भारी निवेश की जरूरत होगी, जिसे आधुनिकीकरण बजट या विशेष मंजूरी के जरिए पूरा किया जा सकता है। सरकार का लक्ष्य केवल हथियार खरीदना नहीं, बल्कि तकनीक का हस्तांतरण सुनिश्चित करना भी है, ताकि भविष्य में भारत खुद इन प्रणालियों का विकास और उत्पादन कर सके।

कुल मिलाकर, आगामी रक्षा बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि यह भारत की दीर्घकालिक सामरिक सोच का प्रतिबिंब भी बनेगा। एक तरफ यह सीमाओं पर मजबूती और सुरक्षा का भरोसा देगा, तो दूसरी तरफ घरेलू रक्षा उद्योग, अनुसंधान और नवाचार को नई ऊर्जा प्रदान करेगा।

मनरेगा पर सियासी संग्राम: तमिलनाडु विधानसभा का प्रस्ताव और केंद्र की नई योजना पर उठे सवाल

(जीएनएस)। चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में शुक्रवार को एक अहम मोड़ देखने को मिला, जब राज्य विधानसभा ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को जारी रखने के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने स्वयं पेश किया और इसके जरिए केंद्र सरकार से स्पष्ट आग्रह किया गया कि ग्रामीण आबादी की आजीविका की सुरक्षा के लिए मनरेगा जैसी योजना को कमजोर न किया जाए। विधानसभा के भीतर हुई चर्चा केवल एक योजना तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों, संसाधनों और ग्रामीण भारत के भविष्य को लेकर चल रहे व्यापक विमर्श का हिस्सा बन गई।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नई ग्रामीण रोजगार योजना 'विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी', जिसे संक्षेप में वीबी-जी राम जी कहा जा रहा है, पर गंभीर आपत्तियां जताईं। उन्होंने कहा कि यह नई योजना मनरेगा की जगह लेने के इरादे से लाई जा रही है, लेकिन इसका स्वरूप और ढांचा ऐसा है, जो ग्रामीण लोगों की आजीविका को सशक्त करने के बजाय उन्हें और अधिक असुरक्षित बना सकता है। स्टालिन के अनुसार, मनरेगा केवल एक रोजगार योजना नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण

अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसने वर्षों से लाखों परिवारों को न्यूनतम आय, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर दिया है।

विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित वीबी-जी राम जी योजना पूरे देश में ग्रामीण लोगों की आजीविका, राज्यों की वित्तीय संरचना, स्थानीय निकायों की आत्मनिर्भरता और विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के रोजगार अवसरों को कमजोर करेगी। उनका तर्क था कि मनरेगा के तहत काम की गारंटी, मजदूरी की पारदर्शी व्यवस्था और पंचायत स्तर पर योजना के क्रियान्वयन ने ग्रामीण समाज में एक स्थायित्व पैदा किया है। इसके विपरीत, नई योजना में राज्यों की भूमिका सीमित करने और केंद्र के नियंत्रण को बढ़ाने की आशंका जताई जा रही है, जो संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ है। स्टालिन ने यह भी रेखांकित किया कि तमिलनाडु ने मनरेगा को जिस कुशलता और पारदर्शिता के साथ लागू किया है, वह पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि चाहे बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हों या लोगों की आजीविका से जुड़ी योजनाएं, तमिलनाडु ने बिना किसी भेदभाव के केंद्र सरकार की पहलों को जमीन पर उतारा है। मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य कई केंद्रीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देश में पहले स्थान पर रहा है और विभिन्न मंत्रालयों से लगातार सराहना भी प्राप्त करता रहा है। इसके बावजूद, केंद्र सरकार द्वारा धनराशि जारी करने में कथित देरी और अनिच्छा राज्य के साथ सौतेले व्यवहार का संकेत देती है। विधानसभा में यह मुद्दा केवल वित्तीय आवंटन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना और महिलाओं की भूमिका पर भी चर्चा हुई। स्टालिन ने कहा कि मनरेगा ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है। बड़ी संख्या में महिलाएं इस योजना के तहत काम कर अपने परिवार की आय में योगदान देती हैं और आत्मनिर्भर बनती हैं। नई योजना में यदि रोजगार की गारंटी कमजोर होती है या काम के अवसर सीमित होते हैं, तो इसका सीधा असर महिलाओं पर पड़ेगा, जो पहले से ही सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही हैं।

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि वह किसी परियोजना की वास्तविक प्रगति के आधार पर धनराशि जारी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु जैसे राज्य, जो योजनाओं को समय पर और प्रभावी ढंग से लागू करते हैं, उन्हें भी धन के लिए इंतजार करना पड़ता है। स्टालिन के अनुसार, केंद्र सरकार जानबूझकर धनराशि की तत्काल रिलीज से बचती है, जिससे राज्य की योजनाओं और विकास कार्यों पर असर पड़ता है। उन्होंने इसे तमिलनाडु के विकास के प्रति सौतेला रवैया बताया।

इस प्रस्ताव के पारित होने के साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि तमिलनाडु सरकार मनरेगा के मुद्दे पर किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। विधानसभा के भीतर सत्तारूढ़ दल के साथ-साथ कई विपक्षी सदस्यों ने भी ग्रामीण रोजगार और आजीविका की सुरक्षा के सवाल पर चिंता जताई। चर्चा के दौरान यह बात उभरकर सामने आई कि मनरेगा ने केवल रोजगार ही नहीं दिया, बल्कि गांवों में जल संरक्षण, सड़क निर्माण, तालाबों की खुदाई और अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण में भी योगदान दिया है, जिसका दीर्घकालिक लाभ ग्रामीण समाज को मिला है।

न्याय की गंभीरता पर सवाल: मानव तस्करी मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। मानव तस्करी जैसे संगीन अपराधों को लेकर न्यायिक संवेदनशीलता और गंभीरता कितनी आवश्यक है, इसका स्पष्ट संदेश सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दिया है। शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को कड़ी फटकार लगाते हुए न सिर्फ मानव तस्करी के एक मामले में दिए गए जमानत आदेश को रद्द कर दिया, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह के अपराधों में "हल्के-फुल्के" दृष्टिकोण की कोई गुंजाइश नहीं है और जमानत देने से पहले आरोपों की प्रकृति, गंभीरता और समाज पर पड़ने वाले प्रभाव पर गहन विचार किया जाना अनिवार्य है।

यह मामला उस समय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा मानव तस्करी के आरोपों का सामना कर रही एक महिला आरोपी को जमानत दे दी गई थी। शीर्ष अदालत की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति विनोद के. चंद्रन शामिल थे, ने इस आदेश को न केवल असंतोषजनक बताया बल्कि इसे न्यायिक विवेक के मानकों पर खरा न उतरने वाला भी करार दिया। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि हाईकोर्ट ने आरोपों की गंभीरता और उनके दूरगामी परिणामों पर विचार किए बिना जमानत देने का आदेश पारित किया, जो कि कानून की भावना के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर विशेष हैरानी जताई कि इतने गंभीर अपराध में जमानत दिए जाने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने उस आदेश को चुनौती देने में कोई तत्परता नहीं दिखाई। पीठ ने राज्य सरकार से सवाल किया कि मानव तस्करी जैसे अपराध, जो न केवल व्यक्तिगत पीड़ितों बल्कि पूरे समाज की आत्मा को झकझोर देते हैं, उनमें सरकार की ओर से इतनी ढिलाई क्यों बरती गई। अदालत ने संकेत दिया कि अभियोजन एजेंसियों और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी केवल मुकदमा दर्ज करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के हर चरण में सक्रिय और सजग रहना चाहिए।

मानव तस्करी को सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार एक संगठित और अमानवीय अपराध के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों का शोषण किया जाता है। यह अपराध केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह मानवाधिकारों पर सीधा हमला है। ऐसे मामलों में आरोपी को जमानत देना तभी उचित हो सकता है, जब अदालत सभी तथ्यों, सबूतों और संभावित खतरों का गंभीरता से मूल्यांकन करे। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में यह भी रेखांकित किया कि यदि अदालतें इस तरह के मामलों में लापरवाही दिखाती हैं, तो इससे न केवल पीड़ितों का न्याय प्रणाली पर भरोसा टूटता है, बल्कि अपराधियों के हौसले भी बढ़ते हैं।

पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए यह स्पष्ट किया कि जमानत आदेश पारित करते समय केवल आरोपी के व्यक्तिगत अधिकारों पर ही नहीं, बल्कि समाज के व्यापक हितों और अपराध की प्रकृति पर भी ध्यान देना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मानव तस्करी जैसे मामलों में आरोपी के प्रभाव, नेटवर्क और पीड़ितों पर पड़ने वाले संभावित दबाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि ऐसे अपराधों में आरोपी को आसानी से जमानत मिलती है, तो इससे जांच और मुकदमे की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है।

इस फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने अप्रत्यक्ष रूप से निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों को यह संदेश दिया है कि वे जमानत जैसे संवेदनशील मामलों में अत्यधिक सावधानी बरतें। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति विनोद के. चंद्रन की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि न्यायिक विवेक का प्रयोग केवल प्रक्रिया पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि न्याय के वास्तविक उद्देश्य को हासिल करने के लिए होना चाहिए।

सरकारी बीमा क्षेत्र में आर्थिक सम्मान का नया अध्याय, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत

(जीएनएस)। नई दिल्ली। केंद्र सरकार के एक अहम फैसले ने सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा और वित्तीय संस्थानों से जुड़े हजारों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन में नई उम्मीद और स्थिरता का संदेश दिया है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतों, भविष्य की सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है, जो वर्षों से देश की आर्थिक और सामाजिक संरचना को मजबूत करने में योगदान देते आए हैं।

सरकार के इस फैसले से 46 हजार से अधिक कार्यरत कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा, जबकि 23,570 पेंशनभोगियों और 23,260 पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी इसका फायदा मिलेगा। इस प्रकार कुल मिलाकर लगभग एक लाख परिवार इस निर्णय से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे। लंबे समय से वेतन और पेंशन संशोधन की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों के लिए यह फैसला एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। खासकर ऐसे समय में, जब महंगाई लगातार बढ़ रही है और स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजमर्रा की आवश्यकताओं का खर्च आम आदमी के बजट पर भारी पड़ रहा है, तब इस तरह का संशोधन आर्थिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक भलाई को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा और वित्तीय संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी न केवल सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाते हैं, बल्कि आपदा, कृषि संकट, स्वास्थ्य बीमा और आर्थिक अनिश्चितता के समय आम जनता को सुरक्षा का भरोसा भी देते हैं। ऐसे में उनके वेतन और पेंशन का समय-समय पर संशोधन न केवल उनका मनोबल बढ़ाता है, बल्कि संस्थानों की कार्यक्षमता और सेवा की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है।

सरकारी सामान्य बीमा कंपनियों के कर्मचारियों के लिए यह वेतन संशोधन एक अगस्त 2022 से प्रभावी माना जाएगा। इसका अर्थ यह है कि कर्मचारियों को संशोधित वेतन के साथ एरियर का भी लाभ मिलेगा, जिससे एकमुश्त आर्थिक राहत मिलने की संभावना है। कुल वेतन व्यय में 12.41 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जो यह दर्शाती है कि सरकार ने वित्तीय अनुशासन और कर्मचारियों की जरूरतों के बीच संतुलन साधने का प्रयास किया है। यह बढ़ोतरी केवल मूल वेतन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इससे जुड़े अन्य भत्तों और भविष्य की पेंशन गणना पर भी इसका असर पड़ेगा।

पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए यह फैसला विशेष महत्व रखता है। सेवानिवृत्ति के बाद आय का मुख्य स्रोत पेंशन ही होती है, और बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में लगातार इजाफा होता है। ऐसे में पेंशन संशोधन से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान के साथ जीवन यापन करने में भी सहायता मिलेगी। पारिवारिक पेंशनभोगियों, खासकर विधवाओं और आश्रितों के लिए यह फैसला एक सुरक्षा कवच की तरह है, जो उन्हें भविष्य की अनिश्चितताओं से कुछ हद तक बचाने का काम करेगा।

नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक जैसे संस्थान देश की आर्थिक रीढ़ माने जाते हैं। नाबार्ड जहां ग्रामीण विकास, कृषि वित्त और सहकारी संस्थाओं के सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाता है, वहीं रिजर्व बैंक देश की मौद्रिक नीति, बैंकिंग व्यवस्था और वित्तीय स्थिरता का प्रहरी है। इन संस्थानों के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन-पेंशन संशोधन यह संदेश देता है कि सरकार उनकी जिम्मेदारियों और योगदान को समझती है और उन्हें उचित मान्यता देना चाहती है।

संपादकीय

संघीय ढांचे पर आंच

भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में सत्ता किसी भी राजनीतिक दल की रही हो, राज्यों में विरोधी दलों की सरकारों व राज्यपालों में टकराव की खबरें दशकों से अखबारों की सुर्खियां बनती रही हैं। जनसरोकारों की रक्षा व राज्य सरकारों की बेलगाम नीतियों पर संतुलन के लिये सृजित यह संवैधानिक पद गाहे-बगाहे विवादों की चपेट में आता रहा है। बहुमत की सरकारों को गिराने के खेल पिछली सदी में भी सुर्खियों में रहे हैं। इस कड़ी में कर्नाटक विधानसभा में घटा ताजा अप्रिय घटनाक्रम भी जुड़ गया। ऐसे में राजभवनों को लोकभवन बनाने को यथार्थ में बदलने की जरूरत भी महसूस की जा रही है। निस्संदेह, कर्नाटक विधानसभा में जो भी कुछ घटा वह राजभवन व निर्वाचित सरकारों के बीच जारी टकराव का एक निचला स्तर ही कहा जा सकता है। खासकर उन राज्यों में जहां राजग की सरकारें नहीं हैं। दरअसल, विधानसभा में मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किए गए पाठ को छोड़कर पारंपरिक संबोधन को केवल कुछ पंक्तियों में सीमित करने के निर्णय के बाद कर्नाटक में एक नया विवाद खड़ा हो गया। जिसका प्रभाव कांग्रेस शासित दक्षिणी राज्य के अलावा भी बहुत दूर तक महसूस किया गया। निर्विवाद रूप से नये साल के पहले सदन की शुरुआत में राज्यपाल का संबोधन एक संवैधानिक परंपरा रही है। यह राज्यपाल के व्यक्तिगत बयान के बजाय राज्य सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं का औपचारिक विवरण होता है। लेकिन सत्र की शुरुआत में राज्यपाल थावरचंद गहलोत अपने द्वारा तैयार किया गया संक्षिप्त भाषण देकर सदन से बाहर चले गए। राज्य की कांग्रेस सरकार ने उन पर केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करने का आरोप लगाया। उल्लेखनीय है यहां यह तल्ख टकराव हाल में तमिलनाडु और केरल विधानसभा में हुए अप्रिय घटनाओं के बाद सामने आया है। विडंबना है कि ऐसी ही असहमतियां, हाल के वर्षों में आम हो चली हैं। जिसे भारत जैसे संघीय लोकतंत्र के लिये शुभ संकेत कदापि नहीं कहा जा सकता है। दरअसल, विभिन्न राज्यों में विपक्षी दलों वाली सरकारों के मुखिया आरोप लगाते रहे हैं कि अधिकतर राज्यों में राज्यपाल का उपयोग केंद्र सरकार के राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने वाले साधन के रूप में ही किया जा रहा है। निस्संदेह, राज्यों में राज्यपालों से उम्मीद की जाती है कि वे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक निष्पक्ष पुल का दायित्व निभाएं। इसमें दो राय नहीं कि किसी भी राज्यपाल को मसविदा संबोधन पर आपत्ति उठाने का अधिकार तो होता है, लेकिन इसके प्रत्युत्तर में संवैधानिक नैतिकता भी अपरिहार्य है। निश्चित रूप से ऐसी किसी भी असहमति को संवाद के माध्यम से हल करने की जरूरत होती है। राज्यपाल और राज्य सरकारों को सदन के भीतर आमने -सामने की भिड़ंत से हर हाल में बचने का प्रयास करना चाहिए। निर्विवाद रूप से किसी भी राज्यपाल और राज्य सरकार का अंतिम लक्ष्य जनता के हितों की रक्षा करना ही होता है। लेकिन किसी भी स्थिति में जब राज्यपाल और राज्य सरकारें विपरीत उद्देश्यों के लिये काम करने लगते हैं, तो शासन की गुणवत्ता का प्रभावित होना स्वाभाविक ही है। निर्विवाद रूप से यह केवल अहम का टकराव मात्र नहीं है। यह सरोकारों के संघवाद की भी एक परीक्षा है। उल्लेखनीय है कि आजकल केंद्र सरकार राजभवनों का नाम बदलकर लोकभवन बनाने की मुहिम चला रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि राजभवन का संबोधन औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। निस्संदेह लोकतंत्र में राजभवन राजतंत्र का पर्याय होने का आभास देता है। लोकतंत्र में लोकभवन सही मायनों में लोक का ही प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन यह लोकभवन शब्द तब ही सार्थक हो सकता है जब जनता के हितों को राजनीतिक टकराव से ऊपर रखा जाएगा। निश्चित रूप से सत्ता के दोनों ही केंद्रों को जनादेश का सम्मान ईमानदारी से करना ही चाहिए। यह भारत जैसे संघीय लोकतंत्र के लिये अपरिहार्य शर्त भी है जिसका पालन राज्यपाल व राज्य सरकारों को पूरा करना ही चाहिए।

चुनौतीपूर्ण दौर में रणनीतिक समझौतों की अनिवार्यता

> "नई विश्व व्यवस्था में द्विपक्षीय संबंधों और मुक्त व्यापार समझौतों का विस्तार ज़रूरी है। लेकिन भारत विरोधी भू-राजनीतिक ताकतों के गठजोड़ों के चलते हमें अपनी सुरक्षा और रणनीतिक गठबंधन बनाने पर भी ध्यान देना चाहिये। अमेरिका के इस्लामाबाद के प्रति नरम रुख और चीन-पाक के मंसूबों से सतर्क रहना होगा वहीं आंतरिक एकजुटता भी अनिवार्य है।

यूएई के राष्ट्रपति का दिल्ली दौरा और हमारे प्रधानमंत्री के साथ उनकी बातचीत, बगल के पड़ोसी के साथ हमारे ठंडे पड़े रिश्तों के बीच ताज़ी हवा के झोंके जैसा है। अब हमारी निगाह यूरोपियन यूनियन के साथ 'सब समझौतों की जननी' (मदर ऑफ ऑल डील्स) पर लगी है जिसके गणतंत्र दिवस तक संपन्न होने की उम्मीद है। यह समझौता यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे संबंधों को नई गति देगा। जिस नई विश्व व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसके मद्देनज़र द्विपक्षीय संबंधों और मुक्त व्यापार समझौतों का विस्तार करना और भी ज़रूरी हो गया है।

अमेरिका उत्तरोतर संरक्षणवादी बनता जा रहा है और पिछली व्यवस्था के बहुत से प्रावधानों को चुनौती दे रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने चीन के अपने हालिया दौरे में चीन के साथ व्यापार समझौते का मसौदा तैयार करते वक्त यही बात कही थी। यह देखते हुए कि हमारे दुश्मन देश हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे, रक्षा/सुरक्षा समझौतों और व्यापार गठबंधनों की ज़रूरत और भी अपरिहार्य बन गई है।

ज़रूरी है कि सत्ता में बैठे लोग इस पर आत्म-मंथन करें। क्या महज इस तथ्य के आधार पर कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत विशाल है और हमारा व्यापार भी बहुत ज़्यादा है, उससे हम अपने पड़ोसी पर अजेयता का अहसास करने लगें? तो यह भी पूछा जाए कि पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को व्हाइट हाउस, पेंटागन, बीजिंग, रियाद, अंकारा आदि में इतना सम्मान क्यों मिल रहा है? पाकिस्तान को चीन से आर्थिक और सैन्य सहायता मिली है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीनी हथियारों ने प्रदर्शन किया, भले ही चीन के साथ हमारा व्यापार 150 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, जबकि इसकी तुलना में पाकिस्तान और चीन का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 15-20 बिलियन डॉलर है। लेकिन उनके पास सीपीईसी (चीन-पाक आर्थिक गलियारा) है जो ग्वादर बंदरगाह के

साथ, मध्य पूर्व और यूरोप के लिए चीनी बेल्ट एंड रोड पहल (बीआरआई) का प्रवेश द्वार है। पाकिस्तान ने शक्सगाम घाटी (पाक अधिकृत कश्मीर में) चीन को सौंप दी थी (जिस पर हमें ऐतराज है) और जहां से होकर काराकोरम राजमार्ग गुज़रता है (जो बीआरआई का अहम हिस्सा है) और यह दोनों देशों के प्रगाढ़ रणनीतिक भाईचारे को दर्शाता है। दूसरी ओर, चीन के साथ हमारा सीमा विवाद है, और चीनी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर दावा करते हैं। इसके मद्देनजर अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी शस्त्रागार में पूर्ववत आर्थिक व सैन्य मदद आती रहेगी।

इसके अलावा, उन्होंने अब सऊदी अरब के साथ एक सुरक्षा समझौता किया है जो ज़रूरत पड़ने पर उन्हें मदद का आश्वासन देता है। एक नए प्रस्तावित त्रिपक्षीय गठबंधन में तुर्की की पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ मिलकर मिनी-नाटो जैसा गठबंधन बनाने की उम्मीद है। याद रखें कि पाकिस्तान के साथ हालिया टकराव के दौरान तुर्की ने ही एकजुटता दिखाने के लिए अपना एक युद्धपोत भेजा था, और कथित तौर पर लड़ाई में उसके बनाए ड्रोनों का भी इस्तेमाल किया गया था। यहां भी, भारत-सऊदी द्विपक्षीय व्यापार 40 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, जबकि पाक-सऊदी व्यापार सिर्फ़ 5 बिलियन डॉलर...फिर भी उनके बीच रक्षा समझौता है। पाकिस्तान लंबे समय से सऊदी अरब को उसकी सुरक्षा ज़रूरतों के लिए सैनिक मुहैया करवाता रहा है और इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है कि वह एकमात्र इस्लामिक देश है जिसके पास परमाणु क्षमताएं हैं। हाल ही में इस्राइल द्वारा कतर में और अमेरिका द्वारा ईरान पर बमबारी को देखते हुए लगता है कि तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच सुरक्षा समझौते के पीछे भू-राजनीतिक मजबूरियां हैं। अल जज़ीरा के एक हालिया लेख के अनुसार, पाकिस्तान एशिया और अफ्रीका के कई देशों को फाइटर जेट बेचने जा रहा है। जेएफ-17 लड़ाकू जेट चीन और पाकिस्तान के संयुक्त उपक्रम में बनाए जा रहे हैं, और इसके नवीनतम ब्लॉक 3 वेरिएंट को 4.5 जेनरेशन के लड़ाकू विमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 25-30 मिलियन डॉलर की अपेक्षाकृत कम कीमत के साथ इसे कई वायु सेनाओं द्वारा आकर्षक विकल्प माना जा रहा है। यह देखते हुए कि भू-राजनीतिक ताकतें खेल कर रही हैं जो केवल व्यापारिक संबंधों पर हावी हो रही हैं, जब तक हम एक सशक्त सक्रिय नीति नहीं अपनाते, हम खुद को उतरोत्तर अलग-थलग पड़ते पा सकते हैं।

अमेरिका अभी भी बड़ी समस्या बना हुआ है, और उसने हाल ही में फिर से इस्लामाबाद की ओर नर्मी भरा रुख अपनाया है। मामलों को और जटिल बनाने के लिए, अमेरिकी टैरिफ और प्रतिबंधों का खतरा हमारे सिर पर मंडरा रहा है। इसके परिणामस्वरूप न केवल हमारे निर्यात में मंदी आई, बल्कि रूस से हमारे तेल आयात में भी भारी कमी करनी पड़ी है।

रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा पड़ा है, और यह हमारे लिए अच्छा नहीं क्योंकि हमारा मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता वही है किंतु फिलहाल उसे अपनी ज़रूरतें पहले पूरी करनी हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे के कारण हमें ईरान के साथ हुए उस समझौते से पीछे हटना पड़ रहा है, जिसके जरिए हमें चाबहार बंदरगाह को विकसित और इस्तेमाल करने में मदद मिली थी, और यह ईरान के साथ बचे-खुचे व्यापार को भी रोक देगा, जो पिछले प्रतिबंधों की वजह से पहले ही काफी कम हो चुका। ईरान पारंपरिक रूप से हमारे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। चाबहार बंदरगाह हमें ईरान और मध्य एशिया तक पहुंच मुहैया कराता है। हालिया खबरों के अनुसार, बंदरगाह के भविष्य पर अमेरिका के साथ चर्चा हो रही है।

आखिर में, कश्मीर का पुराना सवाल पहले की भांति कायम है, चीन के समर्थन वाला पाकिस्तान हमेशा यथास्थिति बदलने के मौके की ताक में रहता है। उनके दावों और बातों को हम केवल दिवास्वप्न कहकर खारिज नहीं कर सकते। चीन सीमाओं पर नागरिक एवं सैन्य बुनियादी ढांचे को नए स्तर पर ले जा रहा है, चाहे अग्रिम सीमांत एयरबेस हों या सड़कें वगैरह, जैसाकि हम भी कर रहे हैं, लेकिन पैमाना अलग है।

बांग्लादेश में बदले हुए राजनीतिक हालात ने मामलों को और जटिल बना दिया तथा आज उनके वरिष्ठ नेता खुलेआम पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से काटने की वकालत करते सुने जा रहे हैं। इस तथ्य के मद्देनज़र कि मणिपुर में स्थिति शांत नहीं और नागालैंड में समस्या अनसुलझी है, यह हमारे पूर्वोत्तर को असुरक्षित और उपद्रवों के लिए खुला छोड़ देता है। लद्दाख में भी अशांति है और मणिपुर की तरह वहां भी त्वरित समाधान जरूरी है। अगर रूस उलझा हुआ है और अपने सहयोगियों की मदद करने में असमर्थ है और अमेरिका प्रतिबद्ध नहीं है, तो हम मदद के लिए किसकी ओर देखेंगे? यह समय चतुर कूटनीति का है ताकि हमारे खिलाफ़ और नए गठजोड़ को रोका जा सके। हम चीन, सऊदी, यूएई, अमेरिका वगैरह के साथ भारी मात्रा में व्यापार करते हैं, हमें अपने रणनीतिक लक्ष्यों के लिए इसका फ़ायदा उठाना चाहिए क्योंकि सभी बड़ी शक्तियों ने व्यापार को एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। मज़बूत विदेश नीति एक मज़बूत एकजुट राष्ट्र की नींव पर आधारित हो। राष्ट्रीय नेतृत्व की ज़िम्मेदारी है कि वह हमें एकजुट रखे, और यह एकता हमारी अपनी गलतियों और स्वार्थी लक्ष्यों के कारण कमज़ोर न पड़ने पाए। केंद्र और राज्यों के बीच अच्छे कामकाजी संबंध होने चाहिए। सभी महत्वपूर्ण मामलों में केंद्र सरकार को चाहिए कि राज्य सरकारों को साथ रखे और उनके नेतृत्व को राष्ट्रीय प्रयासों में शामिल करे। यह रणनीति हमारी सभी आंतरिक सुरक्षा समस्याओं में बहुत कारगर रही है।

भारत की आर्थिक सफलता हमारे पड़ोसियों में ईर्ष्या और दुश्मनी पैदा करती है और इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी सुरक्षा और रणनीतिक गठबंधन बनाने पर कहीं ज़्यादा ध्यान दें।

प्रेरणा

परख के बिना स्वीकार नहीं, यही सच्ची गुरुता

भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में गुरु को केवल ज्ञान देने वाला नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बदल देने वाला तत्व माना गया है। गुरु वह दीपक है जो अंधकार में मार्ग दिखाता है, लेकिन उस दीपक की लौ स्थिर है या नहीं, यह देखे बिना यदि कोई आगे बढ़ जाए तो भटकने की संभावना भी उतनी ही रहती है। इसी गहरे भाव को समझाने वाली यह कथा केवल एक घटना नहीं, बल्कि मनुष्य की मानसिकता, अहंकार, अंधविश्वास और अंततः सच्चे विवेक की परीक्षा का प्रतीक है। एक बार दो पंडित प्रसिद्ध संत दादू जी का सत्संग सुनने और उन्हें अपना गुरु बनाने की प्रबल इच्छा लेकर निकले। दोनों शास्त्रों के ज्ञाता थे, वेद-पुराणों का अध्ययन कर चुके थे और समाज में स्वयं को विद्वान मानते थे। उनके मन में यह भाव था कि यदि दादू जी जैसे महापुरुष को गुरु बना लिया जाए तो उनकी आध्यात्मिक यात्रा पूर्णता की ओर बढ़ जाएगी। लेकिन ज्ञान का बोझ यदि विनम्रता से खाली न हो, तो वही ज्ञान सबसे बड़ा अवरोध बन जाता है। यह बात उन्हें तब समझ आई, जब वे दादू जी की कुटिया की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति दिखाई दिया, जो नंगे सिर बाहर जा रहा था। पंडितों की दृष्टि में यह दृश्य अपशकुन था। शास्त्रों की सतही व्याख्याओं और रूढ़ धारणाओं में उलझे इन पंडितों ने बिना सोचे-समझे उस व्यक्ति को अपशकुन का कारण मान लिया। अपशकुन टालने की तथाकथित धार्मिक प्रक्रिया के नाम पर उन्होंने उस आदमी को दोनों हाथों से थप्पड़ मार दिए। यह दृश्य अपने आप में बड़ा विरोधाभासी था—जो लोग गुरु की खोज में निकले थे, वही करुणा, विवेक और मानवीयता से रहित व्यवहार कर रहे थे। थप्पड़ खाने के बाद भी उस व्यक्ति ने न क्रोध दिखाया, न प्रतिरोध किया। पंडितों ने उससे पूछा कि दादू साहिब का डेरा कहां है। उसने शांति से अंगुली से इशारा करते हुए दिशा बता दी। उसके चेहरे पर न अपमान की शिकायत थी, न बदले की आग। यह मौन सहनशीलता ही असल में गुरुता का पहला संकेत थी, जिसे पंडित अपनी आंखों से देख कर भी समझ नहीं पाए। जब वे डेरे पर पहुंचे तो पता चला कि दादू जी बाहर गए हुए हैं। दोनों पंडित वहीं बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। प्रतीक्षा के क्षणों में उनका आत्मविश्वास धीरे-धीरे अहंकार में बदल रहा था। वे मन ही मन सोच रहे थे कि कैसे वे दादू जी से शास्त्रार्थ करेंगे, कैसे अपने प्रश्नों से उनकी परीक्षा लेंगे। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अक्सर वही लेता है, जिसे हम तुच्छ समझ लेते हैं।

कुछ समय बाद दादू जी लौटे। जैसे ही वे डेरे में आए, पंडितों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने वही व्यक्ति खड़ा था, जिसे उन्होंने रास्ते में थप्पड़ मारे थे। वही शांत चेहरा, वही सरल देह, वही करुण दृष्टि। यह देखकर दोनों पंडितों के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वे थर-थर कांपने लगे। जिस गुरु को वे परखने आए थे, उसी का अपमान वे पहले ही कर चुके थे। अब उनके मन में भय, पश्चाताप और ग्लानि एक साथ उमड़ने लगी।

लेकिन दादू जी के चेहरे पर न क्रोध था, न कटुता। वे मुस्कुराए, ऐसी मुस्कान जिसमें क्षमा भी थी और करुणा भी। उन्होंने सहज भाव से कहा, "लोग दो टके की माटी की हंडिया लेने से पहले उसे टक्कर मारकर देखते हैं। तुम गुरु धारण करने आए हो, तो खूब छककर टकोरो। जब दिल माने, तभी गुरु स्वीकार करो।" यह वाक्य साधारण लग सकता है, लेकिन इसके भीतर आध्यात्मिक चेतना का महासागर छिपा है। दादू जी ने इस एक वाक्य में गुरु और शिष्य के संबंध की पूरी परिभाषा रख दी। गुरु बनने की आकांक्षा रखने वाला यदि अपमान, पीड़ा और अन्याय सह नहीं सकता, तो वह दूसरों के अहंकार को कैसे तोड़ेगा। और शिष्य यदि केवल चमत्कार, पद, प्रतिष्ठा या अंधश्रद्धा के आधार पर गुरु चुनता है, तो वह स्वयं अपने विवेक का अपमान करता है। गुरु को परखना आवश्यक है, लेकिन परख का अर्थ अपमान नहीं, बल्कि सजगता और चेतना है।

इस कथा में पंडितों की गलती केवल थप्पड़ मारना नहीं थी, उनकी गलती थी मनुष्यता से पहले कर्मकांड को रखना। उन्होंने अपशकुन की कल्पना में एक जीवित मनुष्य को साधन बना दिया। दादू जी ने बिना कुछ कहे यह दिखा दिया कि सच्चा गुरु वह है, जो अपने अपमान को भी शिष्य के कल्याण का माध्यम बना ले। जिस क्षण पंडितों ने अपने भीतर के भय और अहंकार को पहचाना, उसी क्षण उनकी असली दीक्षा शुरू हो गई।

गुरुता की पराकाष्ठा यही है कि गुरु शिष्य को उपदेश से नहीं, अनुभव से बदलता है। दादू जी चाहते तो उसी समय पंडितों को उनके अपराध का बोध करा सकते थे, उन्हें डांट सकते थे या मना कर सकते थे। लेकिन उन्होंने मौन और मुस्कान को माध्यम बनाया। यही वह स्तर है, जहां गुरु व्यक्ति नहीं, चेतना बन जाता है।

आज के समय में यह कथा और भी प्रासंगिक हो जाती है। हम अक्सर बाहरी आडंबर, वेशभूषा, भाषण और सोशल पहचान के आधार पर गुरु चुन लेते हैं। लेकिन सच्चा गुरु वही है, जो हमारे अहंकार को बिना तोड़े, उसे गलाकर बहा दे। और सच्चा शिष्य वही है, जो आंख मूंदकर नहीं, बल्कि जाग्रत विवेक के साथ गुरु को स्वीकार करे।

दादू जी का यह कथन हमें यह भी सिखाता है कि गुरु और शिष्य का संबंध बाजार का सौदा नहीं है। जैसे मिट्टी की हंडिया को टक्कर मारकर परखा जाता है, वैसे ही गुरु को भी जीवन की कसौटी पर कसना चाहिए। लेकिन यह कसौटी भीतर की होनी चाहिए, बाहर की नहीं। जब दिल माने, जब अंतरात्मा स्वीकार करे, तभी गुरु धारण करना चाहिए।

अंततः यह कथा हमें यह समझा देती है कि गुरुता की ऊंचाई वहां शुरू होती है, जहां अहंकार समाप्त होता है। जहां अपमान भी शिक्षा बन जाता है और पीड़ा भी करुणा में बदल जाती है। दादू जी ने न केवल दो पंडितों को, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी यह सिखा दिया कि गुरु को खोजने से पहले, अपने भीतर के पंडित को शांत करना जरूरी है। तभी गुरु वास्तव में गुरु बनता है और शिष्य सच में शिष्य।

दुनिया के लिए प्रेरक बनता भारत का चुनावी तंत्र

स्वाधीनता के बाद जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमने अपनाया, वह हमारी अपनी नहीं, पश्चिम से आयातित है। दिलचस्प है कि आज यही व्यवस्था दुनियाभर में शासन की बेहतर प्रणाली के रूप में स्वीकार्य है। इसकी बुनियाद में इंग्लैंड की सन् 1215 में हुई मैग्नाकार्टा की संधि है। आज का लोकतंत्र इसी संधि से निकले कानूनों और परंपराओं से विकसित हुआ है। जबकि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल में भारतीय दिलों की पारंपरिक लोकतांत्रिक सोच है। दुर्भाग्य से भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली की महत्ता को दुनिया हाल तक स्वीकार करने से हिचकती रही है। ऐसे माहौल में अंतरराष्ट्रीय लोकतांत्रिक एवं चुनावी सहायता संस्थान की अगुआई भारत को मिलना मामूली बात नहीं है। अंग्रेजी में इस संस्थान को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेटिक एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस यानी आईडीईए के नाम से जाना जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि भारतीय लोकतंत्र की अहमियत वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य हो रही है। वैश्विक लोकतांत्रिक परिदृश्य के लिहाज से भारत को मिली अगुआई ऐतिहासिक है। 1995 में 14 देशों द्वारा स्थापित इस संगठन के सदस्य देशों की संख्या अब 37 हो चुकी है। संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान स्थायी पर्यवेक्षक के तौर पर इस संगठन में शामिल हो चुके हैं। करीब आठ अरब जनसंख्या वाली दुनिया के करीब दो अरब बीस करोड़ पंजीकृत मतदाता इसी संगठन के सदस्य देशों के पास हैं। जिसमें भारत की हिस्सेदारी 99 करोड़ 10 लाख से ज्यादा है। आंकड़ों से साफ है कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। इस लिहाज से देखें तो भारत की अध्यक्षता उसके लिए औपचारिक दायित्व से कहीं ज्यादा वैचारिक नेतृत्व का अवसर हो सकती है। इस संगठन में सदस्य देशों के चुनाव आयोग या चुनाव कराने वाली संस्थाएं ही शामिल होती हैं, लिहाजा भारतीय चुनाव आयोग इस संस्था का सदस्य है। जाहिर है कि इसी नाते अध्यक्षता भी आयोग के ही पास है।

जिस वक्त घरेलू मोर्चे पर भारतीय चुनाव प्रणाली और मशीनरी सवालों के घेरे में है, उसी वक्त भारतीय चुनाव आयोग को इस प्रतिष्ठित संस्था की अगुआई मिली है। घरेलू मोर्चे पर विपक्षी दलों की ओर से चुनाव आयोग पर कभी वोट चोरी का आरोप लगाया जाता है तो कभी नकारा बताया जाता है। ऐसे वातावरण में चुनाव आयोग को आईडीईए की अध्यक्षता मिलना सामान्य बात नहीं, बल्कि भारतीय चुनाव प्रणाली की वैश्विक स्वीकृति और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। दुनिया अब तक लोकतंत्र को "पश्चिमी मॉडल" के चश्मे से ही देखती रही है। जबकि इसके मूल में लोकतांत्रिक आत्मा नहीं, बाजार केंद्रित राजनीतिक ढांचा है, जहां व्यक्ति की बजाय संस्थाओं की स्वाधीनता और संसदीय परंपराओं पर जोर है। संचार और सूचना क्रांति एवं आर्थिक बदलावों के चलते आज का मतदाता बेहद जागरूक हो चला है। वह अपनी निजी राय की अहमियत की भी चाहत रखता है। इस वजह से पश्चिमी मॉडल वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर सोच बदली है। भारतीय लोकतंत्र और चुनावी व्यवस्था अगर तनकर खड़ी है, तो उसके पीछे इन वैचारिक बदलावों का बड़ा योगदान है। एक अरब की भारी-भरकम मतदाता संख्या वालेभारतीय चुनावी तंत्र में भागीदारी बढ़ना मामूली बात नहीं है। इसे भारतीय चुनावी तंत्र की लचीली किंतु मजबूत व्यवस्था की सफलता के रूप में भी देखा जाना चाहिए।

भारतीय चुनावी प्रबंधन में बढ़ते नवाचार, डिजिटल चुनावी प्रबंधन पर जोर, दिव्यांग और दूरस्थ मतदाताओं तक बढ़ती पहुँच, के लिए चुनाव आयोग की सोच ज्यादा जिम्मेदार है। चुनावी साक्षरता बढ़ाने को लेकर चुनाव आयोग ने जितने प्रयोग किए हैं, वैसा उदाहरण कहीं और नहीं दिखता। विपक्षी सवालों के बावजूद चुनावों में अगर मतदाता भागीदारी बढ़ी है, तो माना जा सकता है कि चुनाव आयोग के प्रति भरोसा कम नहीं हुआ है। इस लिहाज से देखें तो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहुंच पुस्तकालयों और विमर्श के संस्थागत मंचों की बजाय बूथ और अंतिम व्यक्ति तक बढ़ी है। इस संदर्भ में चुनाव आयोग की अध्यक्षता में 21 से 23 जनवरी के बीच आईडीईए देशों के चुनाव प्रमुखों और अधिकारियों की होने जा रही बैठक बेहद अहम हो जाती है। माना जा रहा है कि आयोग से दुनियाभर के अधिकारी जानना चाहेंगे कि मतदाताओं की भारी संख्या के बावजूद आयोग उन तक कैसे पहुंचता है और चुनाव प्रणाली की पवित्रता कैसे बरकरार है।

चुनावी पवित्रता की नाभि-नाल पारंपरिक लोकतांत्रिक प्रणाली से जुड़ी है। प्राचीन भारत का बज्जि गणतंत्र आधुनिक प्रणाली से कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक और लोकोन्मुखी था। दक्षिण भारत के दसवीं सदी के चोल शासकों ने ग्रामीण शासन व्यवस्था के लिए जो व्यवस्था अपना रखी थी, उसे आधुनिक राजनीति विज्ञानी भी बेहतरीन प्रणाली मान रहे हैं। मैग्नाकार्टा के कुछ साल पहले कर्नाटक में लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक संत बसवेश्वर ने जिस अनुभव मंडपम् की स्थापना की थी, उसमें समाज के हर वर्ग के लोग धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर खुलकर चर्चा करते थे और एक परिणति तक पहुंचते थे। राजनीति शास्त्री इसे आधुनिक संसद का प्रथम स्वरूप मानते हैं। आज हमारी चुनाव प्रणाली मजबूत है तो इसकी एक वजह हमारी यह परंपरा भी है।

वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक राष्ट्रों के समक्ष चुनौतियां बढ़ी हैं। जिनके लिए भारत का अनुभव प्रेरक हो सकता है। वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र के लिए ध्रुवीकरण, दुष्प्रचार और साइबर हस्तक्षेप, चुनावी धन में पारदर्शिता की कमी एवं युवाओं की घटती रुचि खतरा बन रही हैं। इसमें जनमत को प्रभावित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल ने कोढ़ में खाज का काम कर रहा है। ऐसे माहौल में भारत अंतरराष्ट्रीय मंच पर चुनावी लिहाज से अपने सफल मॉडल आधारित अनुभव से लोकतांत्रिक राष्ट्रों की चुनाव प्रणाली के लिए प्रेरक हो सकता है।

अभियान

भक्ति की ऋतु में शब्दों का उत्सव: भारतीय साहित्य में बसंत पंचमी का आत्मिक प्रवाह

भारतीय चेतना में बसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं है, यह भीतर के सूने आंगन में दीप जलने का क्षण है। यह वह समय है जब प्रकृति और भक्ति एक-दूसरे में घुलकर ऐसा रस रचती हैं, जिसमें शब्द स्वयं प्रार्थना बन जाते हैं। माघ की तपती शीतलता जब धीरे-धीरे विदा लेती है और धरती पीले रंग में स्नान करने लगती है, तब बसंत पंचमी आती है—माँ सरस्वती की कृपा, ज्ञान की उजास और हृदय की कोमलता लेकर। इस दिन न केवल ऋतु बदलती है, बल्कि मनुष्य के भीतर भी कुछ बदलने लगता है। भारतीय साहित्य ने इस परिवर्तन को सदियों तक देखा है, जिया है और भक्ति के भाव में ढालकर पीढ़ियों को सौंपा है।

संस्कृत साहित्य के आरंभिक स्वर में ही बसंत पंचमी की भक्ति छिपी हुई मिलती है। महाकवि कालिदास जब बसंत का चित्रण करते हैं, तो वह केवल सौंदर्य का उत्सव नहीं होता, बल्कि सृष्टि के प्रति एक मौन नमन होता है। उनके लिए पुष्पों का खिलना, पवन का बहना और कोकिल का गाना—सब ईश्वर की लीला के अंग हैं। बसंत यहाँ किसी बाहरी देवता का पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति में व्याप्त उस परम सत्ता का अनुभव है, जिसे शब्दों में बाँधना कठिन है। कालिदास का काव्य पढ़ते हुए लगता है मानो कवि ने प्रकृति को ही अपना आराध्य मान लिया हो। यही भक्ति का पहला स्वर है—जहाँ श्रद्धा बिना मूर्ति के भी पूर्ण हो जाती है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जयदेव के काव्य में बसंत पंचमी प्रेम और भक्ति के संगम का रूप ले लेती है। गीतगोविंद में बसंत केवल ऋतु नहीं, राधा-कृष्ण के दिव्य मिलन की भूमिका है। यहाँ श्रृंगार सांसारिक न रहकर आध्यात्मिक हो जाता है। मलय पवन की शीतलता, कोकिल की मधुर कूक और कुंजों की हरियाली—सब मिलकर कृष्ण की उपस्थिति का आभास कराते हैं। जयदेव का भक्त प्रेम में डूबकर ईश्वर को पाना चाहता है। बसंत पंचमी यहाँ यह सिखाती है कि भक्ति कठोर तपस्या से ही नहीं, प्रेम की कोमलता से भी उपजती है। जब हृदय में माधुर्य भर जाता है, तब वही माधुर्य ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग बन जाता है।

भक्ति काल में आते-आते बसंत पंचमी का स्वर और अधिक जनजीवन से जुड़ जाता है। सूरदास के पदों में बसंत यमुना के तट पर उतर आता है। वृंदावन की गलियों में कोकिल की कुहूँ केवल ऋतु का संदेश नहीं देती, वह कृष्ण के आगमन की सूचना बन जाती है। सूर के लिए बसंत पंचमी वह क्षण है जब सारा ब्रज कृष्णमय हो उठता है। गोपियाँ, वन, उपवन और नदियाँ—सब भक्ति में लीन हो जाते हैं। यह भक्ति किसी शास्त्र की व्याख्या नहीं, बल्कि भावों की बाढ़ है। सूर का साहित्य बताता है कि जब भक्ति लोकजीवन में उतरती है, तब वह पर्व बन जाती है, उत्सव बन जाती है।

इसी काल में बसंत पंचमी का संबंध माँ सरस्वती से और अधिक गहराता है। ज्ञान, कला और वाणी की आराधना इस दिन एक सामूहिक साधना का रूप ले लेती है। कवि, गायक और साधक सब अपने-अपने ढंग से सरस्वती को स्मरण करते हैं। साहित्य में यह दिन सृजन की प्रेरणा बन जाता है। ऐसा लगता है मानो शब्द स्वयं देवी की कृपा से उतर रहे हों। भक्ति यहाँ मौन नहीं रहती, वह रचना बन जाती है।

मध्यकाल में जब सूफी परंपरा और भक्ति धारा एक-दूसरे से आलिंगन करती हैं, तब बसंत पंचमी मानवीय एकता का पर्व बन जाती है। अमीर खुसरो का बसंत गीत केवल प्रकृति का वर्णन नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति प्रेम का इज़हार है। निजामुद्दीन औलिया के शोक को हरने वाला बसंत उत्सव यह दिखाता है कि भक्ति का रंग पीला हो या केसरिया, उसका मूल एक ही होता है—प्रेम। खुसरो के शब्दों में सरसों का फूल खिलना भी इबादत बन जाता है। यहाँ बसंत पंचमी मंदिर और मस्जिद की सीमाओं से बाहर निकलकर मानव हृदय में प्रवेश करती है। यह भक्ति का वह रूप है, जहाँ संगीत, कविता और उल्लास सब एक साथ नमाज़ भी हैं और आरती भी।

आधुनिक युग में आते-आते साहित्य का स्वर बदलता है, लेकिन बसंत पंचमी की भक्ति समाप्त नहीं होती, वह नया रूप ले लेती है। सुमित्रानंदन पंत के यहाँ बसंत धरती की आत्मा की तरह आता है। यह प्रकृति के प्रति कृतज्ञता की भक्ति है। उनके शब्दों में बसंत कोई देवी नहीं, बल्कि जीवन का सहचर है, जो मनुष्य को फिर से कोमल बनाता है। यह भक्ति शोर नहीं मचाती, यह चुपचाप मन को निर्मल करती है।

नागार्जुन की कविताओं में बसंत पंचमी खेतों में उतर आती है। आम की मंजरियाँ, नई पत्तियाँ और हवाओं की गंध—सब जीवन के प्रति श्रद्धा जगाते हैं। यह भक्ति किसी आसन पर बैठकर नहीं होती, यह मिट्टी में काम करते हुए उपजती है। नागार्जुन का साहित्य यह सिखाता है कि जब मनुष्य धरती से जुड़ता है, तब वह अनायास ही ईश्वर के निकट पहुँच जाता है। बसंत पंचमी यहाँ श्रम और सृजन का उत्सव बन जाती है।

केदारनाथ अग्रवाल की बसंती हवा तो जैसे स्वयं साधक बनकर चलती है। वह बंधनों को नहीं मानती, वह खेतों, नदियों और गलियों में बेखौफ बहती है। यह हवा भक्ति की उस धारा का प्रतीक है, जो डर और जड़ता को तोड़ती है। यह निष्क्रिय श्रद्धा नहीं, बल्कि जाग्रत साधना है। केदार की कविता में बसंत पंचमी साहस का भी पर्व बन जाती है।

सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' के यहाँ बसंत पंचमी एक विशेष आभा ग्रहण कर लेती है। उनका जन्म इसी दिन हुआ और उनका काव्य भी इसी ऋतु की तरह विद्रोही और नवसृजनकारी है। निराला का बसंत देवी की तरह आता है, लेकिन वह शांत नहीं, जाग्रत है। वह कवि को पुकारती है कि उठो, जड़ताओं को तोड़ो, नए जीवन का निर्माण करो। यह भक्ति केवल समर्पण की नहीं, परिवर्तन की भी है। निराला की कविता में सरस्वती की वीणा के साथ शक्ति का स्वर भी गूंजता है।

इस तरह भारतीय साहित्य में बसंत पंचमी की यात्रा केवल कालक्रम नहीं, बल्कि भक्ति की निरंतर धारा है। यह धारा कभी श्रृंगार बनकर बहती है, कभी कृष्ण प्रेम में, कभी सूफी समन्वय में, कभी प्रकृति आराधना में और कभी सामाजिक जागरण में। बसंत पंचमी हमें यह विश्वास दिलाती है कि जीवन में चाहे कितनी ही शीत क्यों न हो, अंततः चेतना का बसंत अवश्य आता है। यह पर्व ज्ञान, प्रेम और एकता का संदेश देता है।

आज भी जब बसंत पंचमी पर सरस्वती वंदना की जाती है, जब पीले फूल चढ़ाए जाते हैं और कविताएँ गुनगुनाई जाती हैं, तब हम अनजाने ही इस पूरी साहित्यिक और भक्ति परंपरा का हिस्सा बन जाते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि शब्द केवल अभिव्यक्ति नहीं, साधना भी हो सकते हैं। जब साहित्य भक्ति के मार्ग से होकर गुजरता है, तब वह आत्मा को छू लेता है। बसंत पंचमी उसी स्पर्श का नाम है—एक ऐसा स्पर्श, जो सदियों से भारतीय मन को जाग्रत करता चला आ रहा है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

कठुआ में सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी जैश का कुख्यात कमांडर उस्मान ढेर

(जीएनएस)। जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षाबलों ने आतंकवाद के खिलाफ जारी अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के कुख्यात कमांडर उस्मान को मुठभेड़ में मार गिराया। यह कार्रवाई शुक्रवार शाम बिलावर क्षेत्र में उस समय अंजाम दी गई, जब सुरक्षा एजेंसियों को इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने पूरे इलाके को घेरकर सघन तलाशी अभियान शुरू किया। इसी दौरान आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उस्मान मारा गया।

सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, उस्मान लंबे समय से जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद फैलाने की साजिशों में शामिल था और पिछले तीन से चार वर्षों से डोडा, उधमपुर और कठुआ बेल्ट में सक्रिय था। वह इन पहाड़ी और जंगली इलाकों की भौगोलिक स्थिति से भली-भांति परिचित था, जिसका फायदा उठाकर वह लगातार ठिकाने बदलता रहता था। इसी कारण पहले भी सुरक्षाबलों के साथ उसकी कई बार मुठभेड़ हो चुकी थी, लेकिन हर बार वह घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों का सहारा लेकर बच निकलने में सफल रहा। इस बार हालांकि सुरक्षाबलों ने पूरी रणनीति और सतर्कता के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया और उसेने का कोई मौका नहीं मिला।

मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है। सबसे अहम बरामदगी अमेरिका में बनी अत्याधुनिक एम-4 असॉल्ट राइफल की है, जो आतंकियों की बढ़ती मारक क्षमता और उन्हें मिल रहे अंतरराष्ट्रीय स्तर के हथियारों की ओर इशारा करती है। इसके अलावा मैगजीन, कारतूस और अन्य सैन्य साजो-सामान भी मौके से मिला है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की गहन जांच कर रही हैं कि यह हथियार सीमा पार से किस तरह और किन माध्यमों के जरिए आतंकियों तक पहुंचा। यह बरामदगी एक बार फिर इस बात को रेखांकित करती है कि सीमा पार से आतंकवाद को लगातार समर्थन मिल रहा है।

आईजीपी जम्मू ने आतंकी उस्मान के मारे जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि यह कार्रवाई जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद के खिलाफ चल रहे अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उनके मुताबिक, उस्मान जैश-ए-मोहम्मद के स्थानीय नेटवर्क का अहम हिस्सा था और वह युवाओं को गुमराह कर संगठन में शामिल करने के प्रयासों में भी लगा हुआ था। उसके मारे जाने से न केवल आतंकी संगठन की कमर टूटी है, बल्कि इलाके में सक्रिय उसके सहयोगी नेटवर्क पर भी गहरा असर पड़ेगा। आईजीपी ने यह भी कहा कि सुरक्षाबल पूरी तरह सतर्क हैं और क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से बिलावर और आसपास के इलाकों में आतंकी गतिविधियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां विशेष रूप से सतर्क थीं। बीते सप्ताह ही सुरक्षाबलों की संयुक्त टीम ने इसी क्षेत्र में आतंकियों के तीन ठिकानों का भंडाफोड़ किया था, जहां से आपत्तिजनक सामग्री और आतंकियों के छिपने के पुख्ता सबूत मिले थे। इससे पहले भी 7 जनवरी और 13 जनवरी को बिलावर क्षेत्र के कहोग और नजोत जंगलों में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। इन लगातार घटनाओं से यह साफ हो गया था कि आतंकी संगठन इस इलाके को अपना नया ठिकाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे नाकाम करने के लिए सुरक्षाबलों ने अपनी मौजूदगी और ऑपरेशन और तेज कर दिए थे।

मुठभेड़ के दौरान स्थानीय प्रशासन ने एहतियातन इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। कुछ समय के लिए आवाजाही पर रोक लगाई गई और लोगों से अपने घरों में ही रहने की अपील की गई। मुठभेड़ समाप्त होने के बाद पूरे क्षेत्र में व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अन्य आतंकी वहां छिपा न हो। स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली और सुरक्षाबलों की इस कार्रवाई की सराहना की, क्योंकि लंबे समय से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ था।

विशेषज्ञों का मानना है कि उस्मान जैसे अनुभवी और खतरनाक आतंकी के मारे जाने से जम्मू क्षेत्र में सक्रिय आतंकी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। यह कार्रवाई न केवल सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और मजबूत खुफिया तंत्र को दर्शाती है, बल्कि यह भी संदेश देती है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किसी भी स्तर पर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। सुरक्षाबलों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी ऐसे ऑपरेशन जारी रहेंगे और आतंकियों तथा उनके मददगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कठुआ में हुई यह मुठभेड़ एक बार फिर इस सच्चाई को सामने लाती है कि जम्मू-कश्मीर में शांति भंग करने की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन सुरक्षाबल पूरी मजबूती के साथ उनका सामना कर रहे हैं। आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां न केवल सीमाओं पर चौकसी बढ़ा रही हैं, बल्कि भीतरू इलाकों में भी अपने नेटवर्क को मजबूत कर रही हैं। उस्मान के खात्मे को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे आने वाले समय में क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों के लिए अहम संवेदनशील निर्णय

गुजरात ग्रामीण गृह निर्माण बोर्ड की विभिन्न आवास योजनाओं में दंडनीय ब्याज माफी

- गुजरात ग्रामीण गृह निर्माण बोर्ड की आवास योजनाओं में दंडनीय ब्याज माफी के लिए वन टाइम राहत योजना
- 6 महीने की समय सीमा में आवास की किस्त की मूल राशि पूरी तरह भरने वालों का दंडनीय ब्याज माफ किया जाएगा
- 9 हजार से अधिक ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को कुल 154 करोड़ रुपए की दंडनीय ब्याज राहत मिलेगी
- मूल राशि पूरी तरह चुका देने वाले लाभार्थियों को मालिकाना हक मिलेगा और वे स्वयं मकान मालिक बनेंगे.

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गुजरात ग्रामीण गृह निर्माण बोर्ड की आवास योजनाओं के लाभार्थियों के व्यापक हित में एक महत्वपूर्ण संवेदनशील निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के इस निर्णयानुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गुजरात ग्रामीण गृह निर्माण बोर्ड की आवास योजना के वे लाभार्थी; जो मूल राशि पूरी तरह चुकाने के लिए सहमत हैं, लेकिन मासिक दो प्रतिशत दंडनीय ब्याज चुकाने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें राहत दी जाएगी।

मुख्यमंत्री के समक्ष ऐसे लाभार्थियों द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस आवास योजना के वे लाभार्थी जो 6 महीनों में अपनी बकाया मूल राशि पूरी तरह चुका देंगे; उन्हें वन टाइम ब्याज माफी योजना के अंतर्गत 2 प्रतिशत दंडनीय ब्याज की वसूली से मुक्त किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के इस निर्णय से लगभग 9,029 ग्रामीण परिवारों को लाभ होगा और उन्हें कुल लगभग 154 करोड़ रुपए की बड़ी दंडनीय राशि की राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के इन परिवारों को उनके नाम पर मकान के मालिकाना हक मिलने से वे वास्तविक अर्थों में अपने स्वयं के मकान के धारक बन जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रत्येक जरूरतमंद नागरिक को स्वयं का आवास उपलब्ध कराने के संकल्प को मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के इस जनहितोन्मुखी निर्णय से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार साकार कर सकेंगे।

फियो के अध्यक्ष श्री एस सी रल्हन की फियो के यूनियन बजट 2026 की सिफारिशें

(जीएनएस)। 1.कॉस्ट और कॉम्पिटिटिवनेस के मुद्दों पर ध्यान दें

प्रस्तावः बजट में इनवर्टेड कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या पर तुरंत ध्यान देना चाहिए, जहाँ कच्चे माल, कंपोनेंट्स या इंटरमीडिएट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी तैयार माल की तुलना में ज़्यादा होती है। फियो निर्यात पर ध्यान देने वाली इंडस्ट्रीज़ द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्य इनपुट पर इम्पोर्ट ड्यूटी को रैशनलाइज़ करने और कम करने की सिफारिश करता है ताकि इनपुट कॉस्ट तैयार प्रोडक्ट ड्यूटी के साथ अलाइन हो जाए।

औचित्यः एक इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर भारतीय निर्यातकों की कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस को काफी कम कर देता है और जमा हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट के ज़रिए कम वर्किंग कैपिटल को लॉक कर देता है। कई सेक्टर्स को इस गड़बड़ी का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, सिंथेटिक यार्न और फाइबर पर तैयार फैब्रिक और गारमेंट्स की तुलना में ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगती है, जिससे टेक्सटाइल और अपैरल वैल्यू चेन पर बुरा असर पड़ता है। इसी तरह, पीसीबी, कनेक्टर और सब-असेंबली जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर इम्पोर्टेड तैयार इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की तुलना में ज़्यादा ड्यूटी लगती है, जिससे घरेलू वैल्यू एडिशन को बढ़ावा नहीं मिलता। केमिकल और प्लास्टिक सेक्टर में, बेसिक रॉ केमिकल और पॉलीमर पर अक्सर डाउनस्ट्रीम फिनिश्ड प्रोडक्ट के मुकाबले ज़्यादा ड्यूटी लगती है, जिससे इंडियन मैन्युफैक्चरर को नुकसान होता है। लेदर और फुटवियर सेक्टर को भी इम्पोर्टेड फिनिश्ड फुटवियर के मुकाबले कंपोनेंट और एक्सेसरीज़ जैसे इनपुट पर ज़्यादा ड्यूटी का सामना करना पड़ता है। रॉ मटीरियल पर ड्यूटी कम करके या रीस्ट्रक्चर करके इन गड़बड़ियों को ठीक करने से प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, वर्किंग कैपिटल का दबाव कम होगा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और इंडिया की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस मज़बूत होगी।

2.शिपिंग सपोर्ट

प्रस्तावः बजट में इंडियन ग्लोबल-स्केल शिपिंग लाइनों के डेवलपमेंट के लिए टारगेटेड पॉलिसी और फिस्कल सपोर्ट देना चाहिए, जिसमें लॉन्ग-टर्म फाइनेंस तक एक्सेस, वायबिलिटी गैप फंडिंग और सपोर्टिव रेगुलेटरी उपाय शामिल हैं।

औचित्यः फॉरेन शिपिंग लाइनों पर इंडिया की भारी डिपेंडेंस एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा फ्रेट कॉस्ट, सप्लाई में रुकावट और ग्लोबल शिपिंग रेट में उतार-चढ़ाव का सामना कराती है। मज़बूत इंडियन शिपिंग कैरियर की कमी इंडिया की ट्रेड रेजिलिएंस और बारगेनिंग पावर को कमज़ोर करती है। इंडियन शिपिंग लाइनों को डेवलप करने से फ्रेट कॉस्ट काफी कम हो सकती है, रिलायबिलिटी बेहतर हो सकती है और लॉजिस्टिक्स पर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल पक्का हो सकता है। अनुमान है कि भारत एक मज़बूत घरेलू शिपिंग इकोसिस्टम के ज़रिए माल ढुलाई में सालाना USD 40-50 बिलियन बचा सकता है। इससे सीधे तौर पर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और भारत के लंबे समय के ट्रेड और लॉजिस्टिक्स सिक्योरिटी को सपोर्ट मिलेगा।

3.फिस्कल और टैक्स इंसेंटिव – अनुसंधान एवं विकास सपोर्ट

प्रस्तावः फियो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 35(2एबी) के तहत इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास खर्च के लिए 200-250% वेटेड टैक्स डिडक्शन को फिर से शुरू करने और कंपनियों से आगे बढ़कर एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप, खासकर एमएसएमई को भी शामिल करने की सिफारिश करता है।

औचित्यः पहले, 200% वेटेड डिडक्शन ने अनुसंधान एवं विकास और इनोवेशन में प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को काफी बढ़ावा दिया है। इसके धीरे-धीरे कम होने से भारत का इनोवेशन इकोसिस्टम ऐसे समय में कमज़ोर हुआ है जब ग्लोबल कॉम्पिटिशन तेज़ हो रहा है। अभी, 38 ओईसीडी देशों में से 35 अनुसंधान एवं विकास के लिए टैक्स इंसेंटिव देते हैं, जिससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को नुकसान होता है। 200% डिडक्शन देने से प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस से जुड़े इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। नॉन-कॉर्पोरेट एंटिटीज़ को एलिजिबिलिटी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एमएसएमई भारत के एक्सपोर्ट इकोसिस्टम की रीढ़ हैं और अक्सर बिना फिस्कल सपोर्ट के अनुसंधान एवं विकास में इन्वेस्ट करने की फाइनेंशियल कैपेसिटी की कमी होती है।

4.ओवरसीज़ मार्केटिंग के लिए टैक्स सपोर्ट

प्रस्तावः बजट में ओवरसीज़ मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ट्रेड फेयर, बायर मीट और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ पर होने वाले खर्च के लिए 200% टैक्स डिडक्शन देना चाहिए, जिससे खासकर एमएसएमई एक्सपोर्टर्स को फायदा हो।

औचित्यः कॉम्पिटिशन करने वाले एक्सपोर्ट करने वाले देशों की तुलना में ग्लोबल मार्केट में भारत के सामान और सर्विस अभी भी ठीक से नहीं दिखाए जाते हैं। ज़्यादा मार्केटिंग और ब्रांडिंग कॉस्ट एक्सपोर्टर्स को—खासकर एमएसएमई को—नए मार्केट में तेज़ी से आगे बढ़ने से रोकती है। बढ़ी हुई टैक्स डिडक्शन एक्सपोर्टर्स को इंटरनेशनल मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने के लिए बढ़ावा देगी और साथ ही असरदार फिस्कल बोझ भी कम करेगी। इस कदम से ब्रांड की विज़िबिलिटी बढ़ेगी, मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और लंबे समय तक ट्रेड सस्टेनेबिलिटी बेहतर होगी।

5.नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए 15% रियायती कॉर्पोरेट टैक्स का विस्तार

प्रस्तावः फियो प्रस्ताव करता है कि नई घरेलू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए सेक्शन 115 बीएबी के तहत 15% रियायती कॉर्पोरेट टैक्स दर को 31 मार्च, 2024 की पिछली कट-ऑफ तारीख से कम से कम पांच साल और बढ़ाया जाए।

औचित्यः ऐसे समय में जब भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग निवेश और सप्लाई-चेन रीलोकेशन के लिए ज़ोरदार मुकाबला कर रहा है, इस रियायती टैक्स व्यवस्था के खत्म होने से मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के तौर पर भारत का आकर्षण कम हो जाता है। इस योजना को बढ़ाने से पॉलिसी में निश्चितता आएगी, निवेश पर टैक्स के बाद रिटर्न बेहतर होगा, और सरकार के मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट-आधारित विकास के उद्देश्यों को मज़बूती मिलेगी। यह उपाय एक सुसंगत और प्रतिस्पर्धी वित्तीय ढांचा बनाकर, नए पूंजी निवेश, रोज़गार सृजन और भारत में उच्च मूल्य-वर्धित मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करके पीएलआई योजनाओं का भी पूरक होगा।

पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर स्टेशन पर ब्लॉक के कारण पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनें प्रभावित

(जीएनएस)। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर स्टेशन पर पुराने पिट लाइन कार्य के कारण पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनें प्रभावित होंगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रभावित ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है:

निरस्त होने वाली ट्रेनें:

1.ट्रेन संख्या 05054 बांद्रा टर्मिनस–गोरखपुर एक्सप्रेस 28 मार्च, 2026 तक निरस्त रहेगी।

2.ट्रेन संख्या 05053 गोरखपुर–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 27 मार्च, 2026 तक निरस्त रहेगी।

शॉर्ट ओरिजिनेट होने वाली ट्रेनें:

1.8 फरवरी, 2026 से 29 मार्च, 2026 तक यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 22921 बांद्रा टर्मिनस–गोरखपुर एक्सप्रेस बलरामपुर स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा बलरामपुर एवं गोरखपुर के बीच निरस्त रहेगी।

2.10 फरवरी, 2026 से 31 मार्च, 2026 तक यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 22922 गोरखपुर–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस बलरामपुर स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा गोरखपुर एवं बलरामपुर के बीच निरस्त रहेगी।

अस्थायी तौर पर विस्तारित ट्रेनें:

1.ट्रेन संख्या 19409 साबरमती–गोरखपुर एक्सप्रेस जिसे पहले 14 फरवरी, 2026 तक थावे तक विस्तारित किया गया था, अब इसे 28 मार्च, 2026 तक थावे तक विस्तारित किया गया है।

2.ट्रेन संख्या 19410 गोरखपुर–साबरमती एक्सप्रेस जिसे पहले 16 फरवरी, 2026 तक थावे से ओरिजिनेट किया जा रहा था, अब इसे 29 मार्च, 2026 तक थावे से ओरिजिनेट किया जाएगा।

"गुजरात राज्य खेल महाकुंभ 4.0 - तैराकी प्रतियोगिता" में अहमदाबाद रेल मण्डल के तीन रेल कर्मचारियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन

(जीएनएस)। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात द्वारा "गुजरात राज्य खेल महाकुंभ 4.0" के अंतर्गत 18 से 19 जनवरी 2026 को वडोदरा में राज्यस्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में राज्यभर के विभिन्न जिलों एवं संस्थानों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपनी खेल प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

इस प्रतियोगिता में पश्चिम रेलवे के मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय अहमदाबाद में कार्यरत तीन रेल कर्मचारियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गौरवपूर्ण उपलब्धियां हासिल की।

- कार्यालय अधीक्षक श्री जयदेव जयेंदु शुक्ला ने 50 मीटर फ्री स्टाइल (28.81 सेकंड), 100 मीटर फ्री स्टाइल (1 मिनट 06 सेकंड) तथा 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक (37.78 सेकंड) स्पर्धाओं में तीन स्वर्ण पदक प्राप्त कर उत्कृष्ट सफलता दर्ज की।
- सीनियर क्लर्क श्री देवांश महेशकुमार परमार ने 400 मीटर फ्री स्टाइल (4 मिनट 17 सेकंड), 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक (58.70 सेकंड) तथा 100 मीटर फ्री स्टाइल (53.29 सेकंड) स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते। इसके अतिरिक्त 4x100 मीटर फ्री स्टाइल रिले एवं 4x100 मीटर मेडले रिले स्पर्धाओं में रजत पदक भी प्राप्त किए।
- कार्यालय अधीक्षक श्री सुमित गवहाणे ने 50 मीटर बटरफ्लाई (32.10 सेकंड) स्पर्धा में स्वर्ण पदक तथा 100 मीटर फ्री स्टाइल (1 मिनट 09 सेकंड) और 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक (36.26 सेकंड) स्पर्धाओं में रजत पदक प्राप्त कर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया।

राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में पश्चिम रेलवे,अहमदाबाद मण्डल के इन तीनों कर्मचारियों द्वारा प्राप्त की गई यह उपलब्धि उनकी कड़ी मेहनत, प्रतिभा एवं खेल के प्रति समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है।

राजकोट का अटल सरोवर बना आकर्षण का केंद्र

अब तक 14 लाख से अधिक लोगों ने की सैर

- राजकोट स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में राजकोट को मिला है अटल सरोवर
- पर्यावरण को ध्यान में रखकर 75 एकड़ में 'रिड्यूस, रियूज और रिसाइकिल' के सिद्धांतों पर हुआ है अटल सरोवर का निर्माण

(जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात ने पिछले ढाई दशक में शहरीकरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2005 को शहरी विकास वर्ष के रूप में मनाकर योजनाबद्ध शहरी विकास की नींव रखी थी। इन 20 वर्षों की विकास यात्रा का जश्न मनाते हुए गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में वर्ष 2025 को शहरी विकास वर्ष घोषित किया। सुव्यवस्थित शहरी नियोजन, दूरदर्शी नीतियों और प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से गुजरात के शहर लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे हैं। विशेषकर, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट जैसे प्रमुख शहरों में बुनियादी सुविधाओं और नागरिक सेवाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। राजकोट शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत विकसित किया गया अटल सरोवर इसका शानदार उदाहरण है।

75 एकड़ में 'रिड्यूज, रियूज और रिसाइकिल' के सिद्धांत पर हुआ है अटल सरोवर का निर्माण

राजकोट स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 930 एकड़ के ग्रीनफील्ड क्षेत्र में तीन तालाबों का आयोजन किया गया है, जिनका उद्देश्य वर्षा जल संचयन के लिए स्टॉर्म वाटर नेटवर्क के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। इनमें से अटल सरोवर (लेक-1) को 75 एकड़ क्षेत्रफल में 'रिड्यूस, रियूज और रिसाइकिल' के '3 आर' सिद्धांतों पर विकसित किया गया है। अटल सरोवर के अंतर्गत 25 एकड़ में 477 मिलियन लीटर जल भंडारण क्षमता विकसित की गई है, जबकि शेष 50 एकड़ में लैंडस्केप (हरित क्षेत्र), मनोरंजन एवं जनसुविधाओं का विकास किया गया है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 136 करोड़ रुपए है, जिसमें 15 वर्षों तक का संचालन और रखरखाव व्यय भी शामिल है। मानसून के दौरान सरोवर में प्राकृतिक रूप से बरसाती पानी का संग्रहण होता है, जबकि गर्मी की सीजन में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत टरशरी ट्रीटमेंट प्लांट (टीटीपी) से रिसाइकिल पानी की आपूर्ति की जाती है। सौराष्ट्र क्षेत्र में अटल सरोवर के जरिए पहली बार किसी प्रोजेक्ट के विकास में '3 आर' सिद्धांतों को लागू किया गया है।

अब तक 14 लाख से अधिक लोगों ने की अटल सरोवर की सैर

अटल सरोवर का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने मार्च, 2024 में किया था। 1 मई, 2024 को गुजरात स्थापना दिवस के अवसर पर इस सरोवर को आम जनता के लिए खोला दिया गया। तब से अब तक 14 लाख से अधिक लोगों ने अटल सरोवर की सैर की है। अटल सरोवर की विशेषता यह है कि इसे आधुनिक मनोरंजन और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया है।

अटल सरोवर के मुख्य आकर्षण

अटल सरोवर आने वाले आगंतुकों के लिए उद्यान, विशेषकर बाल उद्यान, फेरिस व्हील, बोटिंक सुविधा और टॉय ट्रेन जैसे आकर्षण हैं। नागरिकों के लिए पैदल पथ, साइकिल ट्रैक और 600 चार पहिया और 1000 दोपहिया वाहनों के लिए सोलर पैनल युक्त पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, दो एम्फीथिएटर, प्रवेश प्लाजा, पार्टी प्लॉट, 16 दुकानों वाला ओपन फूड कोर्ट, 12 दुकानों वाला क्लोज्ड फूड कोर्ट तथा आरएमसी के स्वामित्व वाले ग्रामहाट के अंतर्गत 42 दुकानें विकसित की गई हैं, जो राजस्व सृजन सुनिश्चित करती हैं। इतना ही नहीं, एक विशाल ध्वज स्तंभ, लाइट एंड साउंड शो सहित अन्य सुविधाएं अटल सरोवर को राजकोट एवं सौराष्ट्र क्षेत्र का एक प्रमुख आकर्षण बनाएंगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ब्लॉक अवधि के दौरान मध्य रेल की सभी छत्रपति महाराज टर्मिनस–बांद्रा–छत्रपति महाराज टर्मिनस एवं छत्रपति महाराज टर्मिनस/पनवेल–गोरेगांव–छत्रपति महाराज टर्मिनस/पनवेल हार्बर लोकल सेवाएं निरस्त रहेंगी। इसके अतिरिक्त, चर्चगेट एवं गोरेगांव स्टेशनों के बीच कुछ स्लो लोकल सेवाएं भी निरस्त रहेंगी। निरस्त की गई ट्रेनों की सूची स्टेशन मास्टर के कार्यालय में उपलब्ध रहेगी। यात्रियों से अनुरोध है कि उपर्युक्त व्यवस्था का कृपया ध्यान में रखकर यात्रा करें।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ब्लॉक अवधि के दौरान मध्य रेल की सभी छत्रपति महाराज टर्मिनस–बांद्रा–छत्रपति महाराज टर्मिनस एवं छत्रपति महाराज टर्मिनस/पनवेल–गोरेगांव–छत्रपति महाराज टर्मिनस/पनवेल हार्बर लोकल सेवाएं निरस्त रहेंगी। इसके अतिरिक्त, चर्चगेट एवं गोरेगांव स्टेशनों के बीच कुछ स्लो लोकल

सेवाएं भी निरस्त रहेंगी। निरस्त की गई ट्रेनों की सूची स्टेशन मास्टर के कार्यालय में उपलब्ध रहेगी। यात्रियों से अनुरोध है कि उपर्युक्त व्यवस्था का कृपया ध्यान में रखकर यात्रा करें।

पश्चिम रेल्वे

विभिन्न कार्य

डेप्युटी चीफ इंजीनियर (कंस्ट्रक्शन), वेस्टर्न रेलवे, मुंबई - 400020 ई-टेंडर नंबर: Dy.CE(C)CCG/356, तारीख 20.01.2026 आमंत्रित करते हैं। काम का नाम: ब्रिज नंबर 46 का विस्तार और जोगेश्वर में शंटिंग नेक का प्रावधान। NIT मूल्य: Rs. 9,47,15,587.62. EMD: Rs. 6,23,600/-. ई-बिड बंद होने की तारीख: ता. 03.02.2026 तक, 15:00 बजे। ई-बिड खुलने की तारीख: तारीख 03.02.2026 को 15:30 बजे। ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएं। 1034

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेल्वे

सामग्री प्रबंधन विभाग

विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति

ई-प्रोक्योरमेंट टेंडर सूचना संख्या S/04/2026 दिनांक 19.01.2026

क्र. नं.	आइटम का संक्षिप्त विवरण	मात्रा	टी.ओ.डी.
31	ट्रक के साथ रूफ माउंटेड एयर कंडीशनिंग सिस्टम	99 सेट	23-फरवरी-26
32	WAP7/WAG9 लोको के नोज सस्पेंशन ड्राइव (MSU ट्यूब) के लिए लेबिरिंथ रिंग का सेट	134 सेट	23-फरवरी-26
33	ग्लार्गिन इंसुलिन 100iu प्रति ml 3ml कार्ट्रिज (प्रति 30 कार्ट्रिज पर एक पेन डिवाइस मुफ्त दिया जाएगा)	37755 नंग	18-फरवरी-26
34	केबल के साथ जम्पर प्लग असेंबली	2534 नंग	17-फरवरी-26
35	ड्रग एल्यूटिंग कोरोनरी स्टेंट सिस्टम- कोबाल्ट क्रोमियम	200 नंग	16-फरवरी-26
36	एंड फ्रेम नॉन ड्राइविंग एंड असेंबली (मशीन से बना हुआ)	63 नंग	16-फरवरी-26
37	मेटैलिक ग्रेडेड जोड़ों के लिए सीलिंग सामग्री (सीलिंग कॉर्ड)	6042 नंग	12-फरवरी-26
38	रियोस्टैटिक ब्रेकिंग रेसिस्टर	40 सेट	12-फरवरी-26
39	रूफ माउंटेड AC पैकेज यूनिट (RMPU)	40 सेट	11-फरवरी-26

शुध्धिपत्र

कृपया टेंडर नोटिस नंबर S-69-2025 दिनांक: 21.11.2025 के लिए सीरियल नंबर 732 पर अंतिम तिथि "27.01.2026" पढ़ें।

कृपया टेंडर नोटिस नंबर S-73-2025 दिनांक: 15.12.2025 के लिए सीरियल नंबर 782 पर अंतिम तिथि "29.01.2026" पढ़ें।

कृपया टेंडर नोटिस नंबर S-73-2025 दिनांक: 15.12.2025 के लिए सीरियल नंबर 784 पर अंतिम तिथि "21.01.2026" पढ़ें।

कृपया टेंडर नोटिस नंबर S-75-2025 दिनांक: 24.12.2025 के लिए सीरियल नंबर 813 पर अंतिम तिथि "03.02.2026" और मात्रा "548 नग" पढ़ें।

विस्तृत नोटिस EMD, खरीद प्रतिबंध और विस्तृत टेंडर शर्तों के संबंध में, कृपया वेबसाइट www.ireps.gov.in और wr.indianrailways.gov.in पर जाएं। 1031

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फॉलो करें: X.com/WesternRly

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल अडालज में आयोजित विशाल समैया महोत्सव में शिक्षापत्री के 200 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उपस्थित रहे : शिक्षापत्री के दर्शन कर धन्यता का अनुभव किया

▶▶ आंतरिक अनुशासन, इनर पीस एवं नैतिक आधार के बिना विकास टिक नहीं सकता : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▶▶ आध्यात्मिक ग्रंथ, पुराण, कथाएं तथा पूजनीय संतों के वचनामृत, धर्म परंपरा हमारी भव्य विरासत हैं : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल शुक्रवार को विक्रम संवत 1882 की वसंत पंचमी के दिन वडताल की पवित्र भूमि पर भगवान स्वामीनारायण द्वारा रचित शिक्षापत्री के 200 वर्ष पूर्ण होने के समैया के उत्सव अवसर पर अडालज में उपस्थित रहे।

इस समैया महोत्सव में सहभागी होकर उन्होंने शिक्षापत्री और भगवान स्वामीनारायण के दर्शन एवं अर्चना कर धन्यता का अनुभव किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वसंत पंचमी अर्थात ज्ञान, साधना, शिक्षण की आराध्य देवी माता सरस्वती की वंदना का दिन है और जोड़ा कि भगवान स्वामीनारायण ने भी समाज को 'शिक्षापत्री' के माध्यम से अनुशासन, संयम, सदाचार और समरसता की ओर ले जाने वाली विचारधारा का शिक्षण देने का युगांतकारी कार्य किया है।

श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि शिक्षापत्री ने धर्म को केवल उपासना तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे व्यावहारिक जीवन में समरसता, एकता और बंधुता से भी जोड़ा है। विश्वनेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' का जो मंत्र दिया है, उसे शिक्षापत्री समैया उत्सव साकार करता है। उन्होंने कहा कि मुझे इस उत्सव में सहभागी होकर संतों के आशीर्वाद तथा आप सभी हरि भक्तों के दर्शन का सौभाग्य मिला है, इसके लिए मैं स्वयं को भाग्यशाली मानता हूँ, मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आध्यात्मिक ग्रंथ, पुराण, कथाएं और संतों के वचनामृत, धर्म परंपरा हमारी भव्य विरासत हैं।

शिक्षापत्री के 200 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर यह समैया महायज्ञ, वेदपाठ के पठन और अखंड धुन से इस आध्यात्मिक विरासत को व्यापक बनाने का अर्थपूर्ण माध्यम है।

साथ ही साथ प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब द्वारा दिए गए 'विरासत भी, विकास भी' के लक्ष्य को साकार करने वाला यह प्रसंग भी है। इस उत्सव में ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और एआई का उपयोग कर लोग शिक्षापत्री के संदेशों को देख एवं समझ सकेंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत के लिए जनहित के 9 संकल्प दिए हैं

पहला संकल्प – जल बचाओ,
दूसरा संकल्प – एक पेड़ मां के नाम,
तीसरा संकल्प – स्वच्छता,
चौथा संकल्प – वोकल फॉर लोकल,
पांचवां संकल्प – देश दर्शन,
छठा संकल्प – प्राकृतिक खेती,
सातवां संकल्प – स्वस्थ और आरोग्यपूर्ण जीवनशैली,
आठवां संकल्प – योग और खेल-कूद को जीवन का हिस्सा बनाना,
नौवां संकल्प – गरीबों की सहायता।

इन संकल्पों का विस्तार से विवरण देते हुए मुख्यमंत्री ने स्वामीनारायण संप्रदाय की सत्संग सभाओं में इन नौ संकल्पों के प्रति जन जागृति फैलाने की अपेक्षा व्यक्त की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को विकसित गुजरात के माध्यम से गति प्रदान करने में सफलता मिले, ऐसी प्रार्थना भगवान स्वामीनारायण से की।

समैया महोत्सव में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वीडियो संदेश का प्रसारण कर सभी हरि भक्तों को शुभकामनाएं दी गईं।

महोत्सव के अवसर पर कालुपुर स्वामीनारायण मंदिर के मुख्य महाराज श्री कौशल्य प्रसादजी तथा श्री राजेंद्र प्रसाद (लालजी) महाराज ने शिक्षापत्री और उसके मूल्यों, गृहस्थ, संत और समाज के लिए आदर्श स्थिति के सिद्धांतों पर मार्गदर्शन दिया। साथ ही उन्होंने शिक्षापत्री के मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए हरिभक्तों से अपील की।

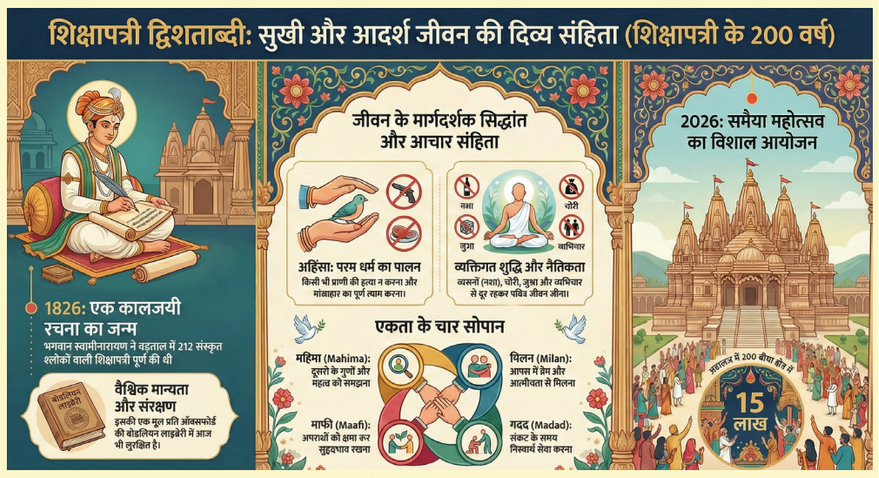

कर्तव्य पथ पर इतिहास और राष्ट्रभक्ति की जीवंत गाथा, गुजरात की झांकी में लहराएगा वंदे मातरम का गौरव

(जीएनएस)। नई दिल्ली। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर निकलने वाली झांकियों में इस बार गुजरात की प्रस्तुति विशेष आकर्षण का केंद्र बनने जा रही है। देश की आज़ादी, राष्ट्रीय चेतना और स्वदेशी आंदोलन की आत्मा को समेटे यह झांकी 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की ऐतिहासिक यात्रा को बेहद भावनात्मक और प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करेगी। यह झांकी केवल एक दृश्य प्रस्तुति नहीं होगी, बल्कि भारत की स्वतंत्रता चेतना, संघर्ष, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की विचारधारा का जीवंत दस्तावेज बनेगी। वंदे मातरम, जो हर भारतीय के मन में देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित करता है, इस झांकी की आत्मा है। यह गीत केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वतंत्रता की चेतना का मंत्र है। गुजरात की झांकी में इसी मंत्र के साथ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के विकास की वह ऐतिहासिक यात्रा दिखाई

जाएगी, जो आजादी की लड़ाई के हर पड़ाव से होकर गुजरी है। झांकी में यह दर्शाया जाएगा कि किस तरह तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के संघर्ष, बलिदान और संकल्प का प्रतीक बना। इस झांकी में विशेष रूप से नवसारी में जन्मी वीरांगना मैडम भीकाजी कामा की यशोगाथा को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है। मैडम कामा ने श्यामजी कृष्ण वर्मा और सरदार सिंह राणा जैसे क्रांतिवीरों के साथ विदेशी धरती पर भारत की आज़ादी की अलख जगाई थी। वर्ष 1907 में पेरिस में उन्होंने जिस ध्वज को पहली बार फहराया था, उस पर 'वंदे मातरम' अंकित था। यही ध्वज बाद में जर्मनी के स्टटगार्ट और बर्लिन में आयोजित इंडियन सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भी लहराया गया। झांकी में मैडम भीकाजी कामा की ध्वज लहराती अर्ध-प्रतिमा को दर्शाया गया है, जिसके नीचे संविधान में सूचीबद्ध सभी भारतीय भाषाओं में 'वंदे मातरम' अंकित है। यह दृश्य भारत की भाषाई विविधता में एकता का सशक्त संदेश देता है।

झांकी के मध्य भाग में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की निर्माण यात्रा को क्रमबद्ध और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसकी शुरुआत वर्ष 1906 से होती है, जब कोलकाता के पारसी बागान में विदेशी वस्तुओं की होली जलाने और स्वदेशी आंदोलन के आह्वान के साथ पहली बार 'वंदे मातरम' लिखा ध्वज फहराया गया था। इसके बाद 1917 में होमरूल आंदोलन के दौरान डॉ. एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा फहराए गए ध्वज का उल्लेख है, जिसने स्वराज्य की मांग को नई दिशा दी। वर्ष 1921 में बेजवाड़ा, जिसे आज विजयवाड़ा के नाम से जाना जाता है, वहां युवा क्रांतिवीर पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए ध्वज को महात्मा गांधी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का प्रसंग भी झांकी में उकेरा गया है।

1931 में पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किए गए तिरंगे को लगभग स्वीकृति मिल गई थी, जिसके केंद्र में चरखा था और जो तीन रंगों में भारत की विविधता और एकता का प्रतीक बना। अंततः 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने चरखे के स्थान पर धर्म चक्र को केंद्र में रखकर तिरंगे को उसके वर्तमान स्वरूप में स्वीकार किया। इस ऐतिहासिक निर्णय के साथ ही स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज अस्तित्व में आया। झांकी में इस पूरे विकासक्रम को आज़ादी के प्रमुख आंदोलनों और घटनाओं के साथ जोड़ा गया है, ताकि दर्शक यह महसूस कर सकें कि तिरंगे का हर रंग और हर प्रतीक संघर्ष और बलिदान की कहानी कहता है।

1.5 लाख करोड़ के कथित बैंक घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, अनिल अंबानी से मांगा जवाब

(जीएनएस)। नई दिल्ली/मुंबई। देश के सबसे बड़े कथित बैंक घोटालों में से एक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए उद्योगपति अनिल अंबानी और उनके समूह से जवाब तलब किया है। शीर्ष अदालत ने करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये के कथित बैंक फ्रॉड की जांच से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अनिल अंबानी और अनिल अंबानी ग्रुप को निर्देश दिया है कि वे अपना काउंटर एफिडेविट दाखिल करें। यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष प्रस्तुत हुआ, जहां अदालत ने पूरे प्रकरण की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सभी संबंधित पक्षों से जवाब मांगा।

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर पहले जारी नोटिस के क्रम में अब केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय को भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे इस कथित बैंक फ्रॉड से संबंधित चल रही जांच की स्थिति से अदालत को अवगत कराएं। अदालत ने कहा कि यदि जांच अभी पूरी नहीं हुई है, तो एजेंसियां अपनी स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में भी

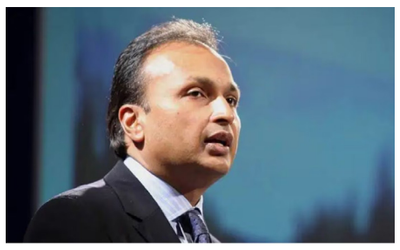

दाखिल कर सकती हैं। कोर्ट का यह रुख इस बात का संकेत माना जा रहा है कि वह इस मामले की निगरानी बेहद गंभीरता से करना चाहती है और जांच प्रक्रिया में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

यह जनहित याचिका पूर्व आईएएस अधिकारी ईएएस सरमा द्वारा दाखिल की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अनिल अंबानी और उनके समूह ने सरकार और बैंकों के कुछ अधिकारियों की कथित मिलीभगत से जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा कीं, जिनके चलते उनकी कई कंपनियां दिवालिया घोषित हो गईं। याचिका में दावा किया गया है कि इस प्रक्रिया के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया गया, जिसकी निष्पक्ष और अदालत की निगरानी में जांच बेहद जरूरी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह मामला केवल वित्तीय अनियमितताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संस्थागत जवाबदेही और सार्वजनिक धन की सुरक्षा का बड़ा सवाल जुड़ा हुआ है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि इतने बड़े पैमाने पर हुए कथित नुकसान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि जांच एजेंसियों की ओर से अब तक की गई कार्रवाई संतोषजनक नहीं पाई जाती है, तो आगे और कड़े निर्देश दिए जा सकते हैं। कोर्ट का यह रुख ऐसे समय में सामने आया है, जब बैंकिंग सेक्टर में बड़े कॉरपोरेट डिफॉल्ट और फ्रॉड के मामलों को लेकर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं और आम जनता के बीच यह धारणा बनी हुई है कि बड़े उद्योगपतियों के मामलों में कार्रवाई अक्सर धीमी रहती है।

अनिल अंबानी समूह की ओर से अब तक इस मामले पर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उनके लिए अपना पक्ष अदालत के सामने रखना अनिवार्य हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस याचिका में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है, तो इसका असर न केवल संबंधित उद्योग समूह पर पड़ेगा, बल्कि बैंकिंग व्यवस्था, नियामक संस्थाओं और सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं।

इस मामले की अगली सुनवाई में सभी पक्षों के जवाब और जांच एजेंसियों की स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट आगे की दिशा तय करेगा। फिलहाल, शीर्ष अदालत का सख्त रुख यह संकेत देता है कि 1.5 लाख करोड़ रुपये जैसे बड़े कथित बैंक फ्रॉड के मामले में जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया को वह किसी भी हाल में कमजोर नहीं पड़ने देगी।

सरकारी वित्तीय संस्थानों के कर्मचारियों को बड़ी सौगात वेतन–पेंशन संशोधन से हजारों परिवारों में राहत

(जीएनएस)। नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) तथा भारतीय रिजर्व बैंक से जुड़े कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक अहम और राहत भरा फैसला लिया है। लंबे समय से प्रतीक्षित वेतन और पेंशन संशोधन को आखिरकार मंजूरी मिल गई है, जिससे न केवल सेवारत कर्मचारियों बल्कि पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनधारकों को भी सीधा लाभ होगा। इस निर्णय को सरकार की सामाजिक सुरक्षा नीति और कर्मचारियों के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस फैसले से देशभर में 46 हजार से अधिक कर्मचारी, करीब 23 हजार पेंशनभोगी और लगभग इतने ही पारिवारिक पेंशनधारक लाभांवित होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के कर्मचारियों के वेतन में 12.41 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है, जो एक अगस्त 2022 से प्रभावी मानी जाएगी। इसका अर्थ यह है कि कर्मचारियों को न केवल बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, बल्कि बीते समय का एरियर भी दिया जाएगा, जिससे एकमुश्त बड़ी राशि उनके हाथ में आएगी।

वेतन संशोधन के तहत मूल वेतन और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही वर्ष 2010 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत सरकार के योगदान को बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है। यह कदम भविष्य की पेंशन सुरक्षा को मजबूत करने वाला माना जा रहा है, क्योंकि इससे सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को अधिक स्थिर और सुरक्षित आय का आधार मिलेगा। लंबे समय से कर्मचारी संगठनों की ओर से इस मांग को उठाया जा रहा था, जिसे अब जाकर स्वीकार किया गया है।

सरकार ने पारिवारिक पेंशनधारकों को भी बड़ी राहत दी है। पारिवारिक पेंशन की दर को एक समान 30 प्रतिशत निर्धारित करने का फैसला लिया गया है। इससे उन परिवारों को विशेष रूप से लाभ होगा, जो सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मचारियों की पेंशन पर निर्भर हैं। इस निर्णय से हजारों परिवारों की मासिक आय में सुधार होगा और उन्हें बढ़ती महंगाई के बीच कुछ आर्थिक संबल मिलेगा। इसी तरह नाबार्ड के ग्रुप 'ए', 'बी' और 'सी' श्रेणी के सभी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में भी लगभग 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी को स्वीकृति दी गई है, जो एक नवंबर 2022 से लागू होगी। इसके साथ नाबार्ड के पेंशनधारकों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी संशोधित दरों का लाभ मिलेगा। ग्रामीण विकास और कृषि वित्त के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाले इस संस्थान के कर्मचारियों के लिए यह फैसला लंबे समय से चली आ रही मांगों का सकारात्मक समाधान माना जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनधारकों के लिए भी एक नवंबर 2022 से पेंशन में वृद्धि को मंजूरी दी गई है।

ईयू जीएसपी अधिसूचना और भारतीय निर्यात पर इसके असर को लेकर स्पष्टीकरण

(जीएनएस)। नई दिल्ली; 23 जनवरी, 2026: फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस (फियो) यूरोपीय संघ के उस अधिसूचना के बारे में हाल की रिपोर्टों पर स्पष्टीकरण देना चाहता है जिसमें भारत से कुछ प्रोडक्ट कैटेगरी पर जीएसपी लाभ वापस लेने की अवधि बढ़ाई गई है।

हालांकि यह बताया गया है कि ईयू को भारत के निर्यात वैल्यू का लगभग 87 प्रतिशत ईयू अधिसूचना में बताई गई बड़ी प्रोडक्ट कैटेगरी के तहत आता है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसका मतलब यह नहीं है कि 87 प्रतिशत भारतीय निर्यात पर ज़्यादा ड्यूटी लगेगी।

सबसे पहले, ईयू अधिसूचना में बड़े प्रोडक्ट ग्रुपिंग का ज़िक्र है, जिसके तहतः (i) कई प्रोडक्ट पर पहले से ही ईयू के एमएफएन (मोस्ट फेवर्ड नेशन) सिस्टम के तहत ज़ीरो कस्टम ड्यूटी लगती है, और इसलिए जीएसपी प्राथमिकताओं को वापस लेने से उन पर कोई असर नहीं पड़ता है; और (ii) इन बड़ी कैटेगरी के तहत कई खास टैरिफ लाइनें लागू नियमों और शर्तों के अधीन ईयू जीएसपी लाभों के लिए योग्य बनी हुई हैं।

दूसरा, यह रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि जीएसपी लाभों को वापस लेना कोई नया कदम नहीं है। मौजूदा अधिसूचना सिर्फ़ प्राथमिकताओं के पहले के निलंबन की वैधता को बढ़ाता है, जो पिछले कुछ सालों से इन प्रोडक्ट ग्रुप के लिए लागू है। इस विस्तार के ज़रिए जीएसपी वापसी के तहत कोई भी अतिरिक्त प्रोडक्ट नए सिरे से नहीं लाए गए हैं।

इसलिए, भारतीय निर्यात पर अधिसूचना का व्यावहारिक असर सीमित है, और निर्यातकों को सलाह दी जाती है कि वे बड़ी प्रोडक्ट कैटेगरी के स्तर के बजाय टैरिफ-लाइन (एचएस कोड) स्तर पर अपनी स्थिति का आकलन करें।

सोना वायदा में 437 रुपये, चांदी वायदा में 6912 रुपये और क्रूड ऑयल वायदा में 129 रुपये की वृद्धि

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 260360.05 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 82193.84 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 178147.99 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का फरवरी वायदा 43784 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 4185.07 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 72302.90 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा 158889 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 159226 रुपये और नीचे में 155248 रुपये पर पहुंचकर, 156341 रुपये के पिछले बंद के सामने 437 रुपये या 0.28 फीसदी की तेजी के संग 156778 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-गिनी जनवरी वायदा 1480 रुपये या 1.14 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 131448 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल जनवरी वायदा 245 रुपये या 1.51 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 16492 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी फरवरी वायदा 158143 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 159527 रुपये और नीचे में 155631 रुपये पर पहुंचकर, 780 रुपये या 0.5 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 157313 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन जनवरी वायदा प्रति 10 ग्राम 159887 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 160000 रुपये और नीचे में 156322 रुपये पर पहुंचकर, 156818 रुपये के पिछले बंद के सामने 1332 रुपये या 0.85 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 158150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 333333 रुपये के भाव पर खूलकर, 339927 रुपये के दिन के उच्च और 327502 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 327289 रुपये के पिछले बंद के सामने 6912 रुपये या 2.11 फीसदी की तेजी के संग 334201 रुपये प्रति किलो हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 6649 रुपये या 2 फीसदी की तेजी के संग 339042 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। जबकि

▶▶ कमोडिटी वायदाओं में 82193 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 178147 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 72302 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 43784 पॉइंट के स्तर पर

चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 6789 रुपये या 2.04 फीसदी की मजबूती के साथ 339265 रुपये प्रति किलो बोला गया। मेटल वर्ग में 4420.48 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा जनवरी वायदा 8.5 रुपये या 0.67 फीसदी की तेजी के संग 1281.55 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता जनवरी वायदा 1.35 रुपये या 0.43 फीसदी की तेजी के संग 313.3 रुपये प्रति किलो हुआ। इसके सामने एल्यूमीनियम जनवरी वायदा 1.1 रुपये या 0.35 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 316.3 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा जनवरी वायदा 65 पैसे या 0.34 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 190.8 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 5451.05 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल फरवरी वायदा 5495 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5574 रुपये और नीचे में 5482 रुपये पर पहुंचकर, 129 रुपये या 2.37 फीसदी बढ़कर 5569 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी फरवरी वायदा 126 रुपये या 2.32 फीसदी की मजबूती के साथ 5568 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस जनवरी वायदा 475 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 475 रुपये और नीचे में 421.7 रुपये पर पहुंचकर, 463.3 रुपये के पिछले बंद के सामने 6.7 रुपये या 1.45 फीसदी घटकर 456.6 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी जनवरी वायदा 8.5 रुपये या 1.83 फीसदी घटकर 456.8 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 960 रुपये के भाव पर खूलकर, 2.3 रुपये या 0.23 फीसदी लुढ़ककर 982 रुपये प्रति किलो बोला गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 44003.93 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 28298.97 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 3780.33 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 266.65 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 31.91 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 323.46 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 613.01 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 4826.10 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 18.02 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 20317 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 97256 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 34664 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 511942 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 63757 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 14354 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 38409 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 105565 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 17420 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 23064 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 43500 पॉइंट पर खूलकर, 44200 के उच्च और 43300 के नीचले स्तर को छूकर, 795 पॉइंट बढ़कर 43784 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल फरवरी 5500 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 74.4 रुपये की बढ़त के साथ 278.8 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.3 रुपये की गिरावट के साथ 28.5 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 157000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 1.5 रुपये की गिरावट के साथ 2487.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 330000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 2564 रुपये की बढ़त के साथ 12105.5 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 4.96 रुपये की बढ़त के साथ 54.77 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.3 रुपये की बढ़त के साथ 9 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल फरवरी 5500 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 48.8 रुपये की गिरावट के साथ 220.8 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 50 पैसे की नरमी के साथ 22 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 155000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 177 रुपये की गिरावट के साथ 1725.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 330000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 4000 रुपये की गिरावट के साथ 7936 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 3.16 रुपये की गिरावट के साथ 42.04 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 83 पैसे की नरमी के साथ 3 रुपये हुआ।